Issue Feb 2022

For Private Circulation Only

INDIA NEWS BY FII

Monthly News Letter For Global Audience

Rajpath, India

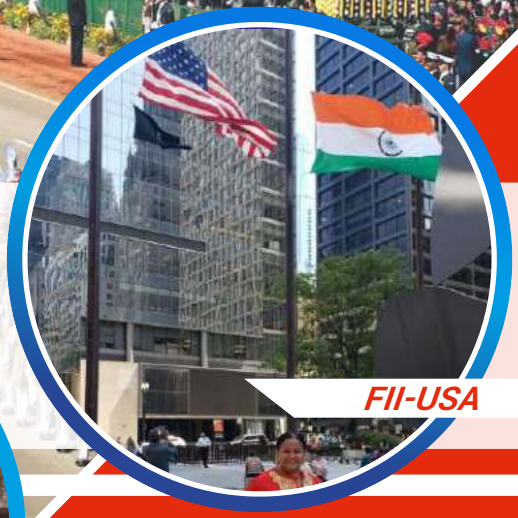

FII-USA

FII-Nigeria

Indian Dream Global Action

आज़ादी का अमृत महोत्सव

www.fii.org.in

Restores the Mobility Naturally

जोड़ों के दर्द की
असरकारक औषधि

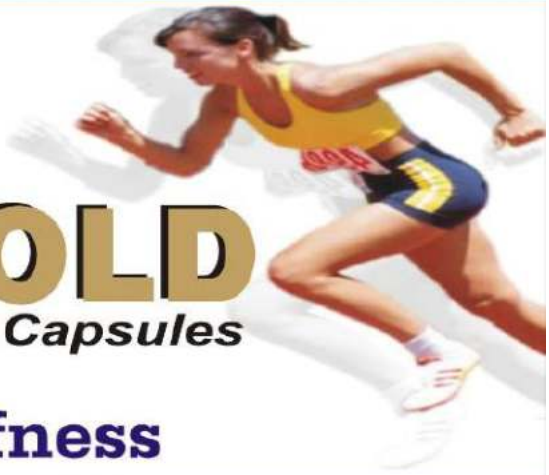

RUMANIL GOLD
Capsules

For Joint Pains and Stiffness

DHARMANI
HEALTH & FITNESS CO.

Hair Tone
Oil

Hair fall Solution

DHARMANI
HEALTH & FITNESS CO.

Pushpile

Pushpile
Capsules

The Perfect Remedy for
External or Internal Piles

DHARMANI
HEALTH & FITNESS CO.

CHIEF EDITOR

Mr. Hitender Mehta , FCS,FCA, L.L.B

MANAGING EDITOR

Mr. Uditendu Verma

EDITORIAL BOARD

Dr. Shailendra Vyas

Mr. Sanjiv Arora

Dr. Dravya Jain

Mr. Harsh Datt

Managed & Published on the behalf of
Federation of Indian Industry
Email: office@fiiorg.in
uditendu@gmail.com
Mob: +91-9599935527

From the Desk of

Mr. Deepak Jain
Director General
Federation of Indian Industry

The Indian budget 2022-23 was presented in the parliament. The budget kept the ethos of the 'Antodaya' in mind while thinking global but acting local principle in picture. Despite the pandemic, the anticipated above 9% growth and a largest ever GST since its inception indicates that we are moving in the right direction. Its the time for taking the reforms a step further.

The Nal se Jal scheme and the PM housing scheme will make a long desired change in rural and social segment. The PM Gati Shakti, incentives for startups like period of incorporation extended by a year to 2023 to avail of tax benefits, Agri-startups to get funding from NABARD, new Vande Bharat Trains, increased allocation for emergency Credit Guarantee Scheme for MSME, PM E-vidya Program, E-passports with digital chips, battery swapping policy, highways, Sovereign Green Bonds for mobilising green energy and to deduce carbon density etc. are going to usher the country in the next level of economic growth. The proposal to set up Centre for accelerated corporate Exit will help the country become a startup leader in innovation and growth. FII has identified biotechnology as one of the most promising fields that can help India target a bigger goal of USD 10 trillion economy or more which is not impossible for the largest democracy of the world. The time is ripe to set the stage ready for this industrial sector.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

OUR INSPIRATIONS

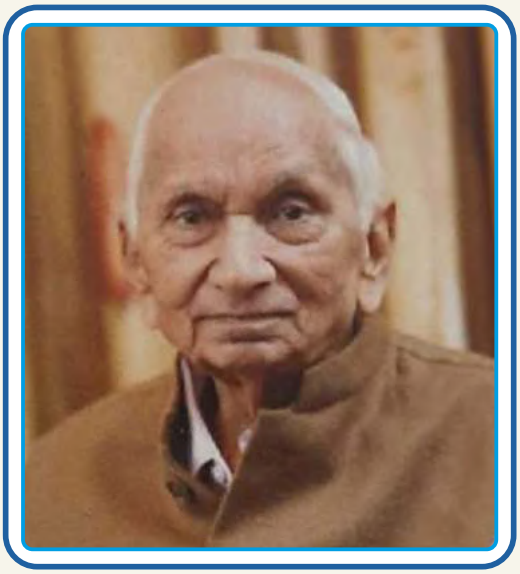

Padma Bhushan

L. Sh. Darshan Lal Jain

Padma Vibhushan

L. Smt. Shusma Swaraj

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

आज़ादी का अमृत महोत्सव

YouTube LIVE

Every Thursday

18:00 PM (IST)

Talk with an expert show

HOSTED BY

MR.SANJEEV ARORA

DR. DRAVYA JAIN

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

BIOHEAVEN 360

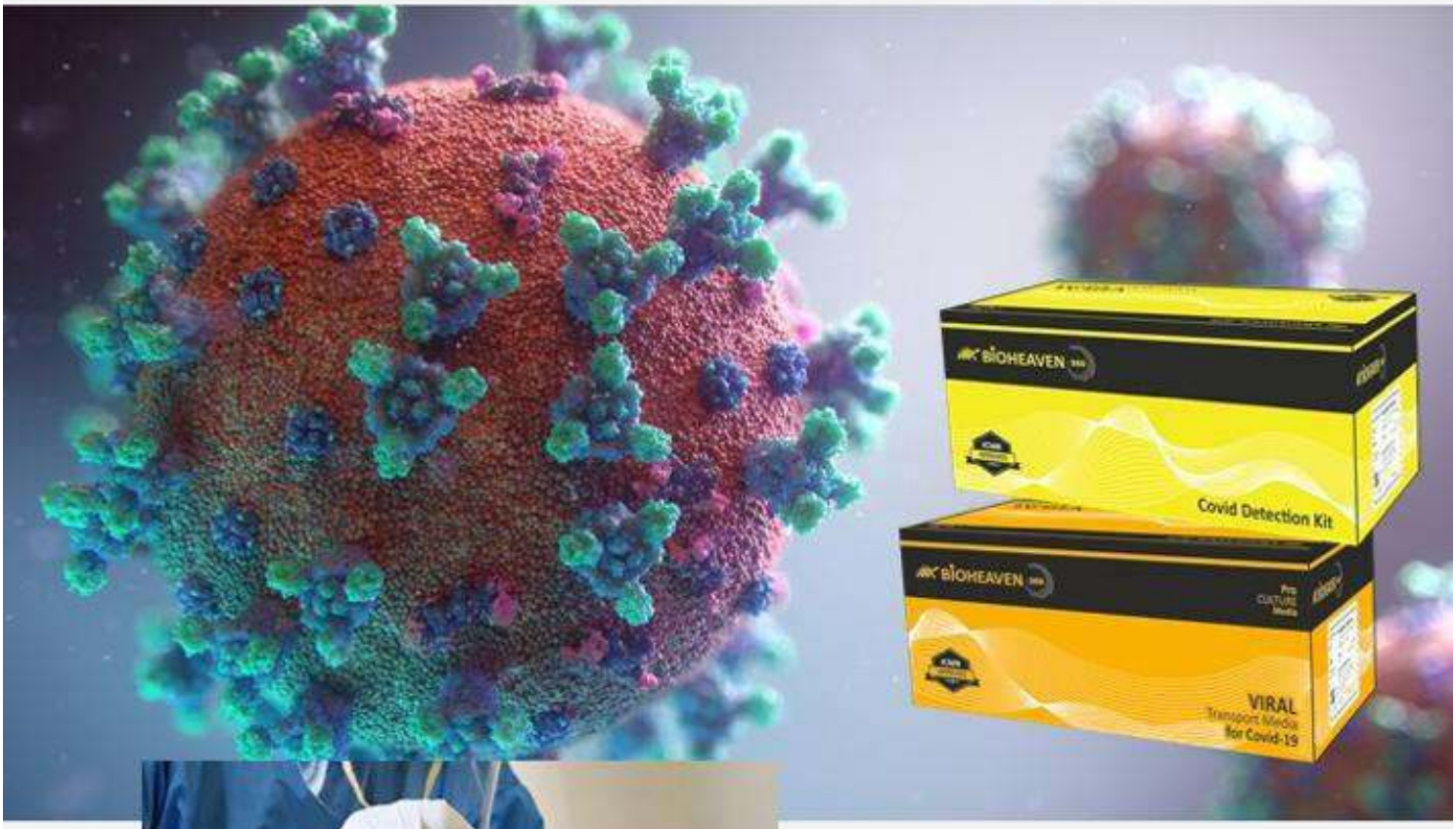

PROUDLY DIAGNOSING INDIA

WITH MADE IN INDIA

www.bioheaven360.com

+91 88 600 90727

BIOHEAVEN360 GENOTEC PVT LTD

New Delhi.India

FII IN MEDIA

आटोमोबाइल उद्योग को पटरी पर लाने के लिये बजट में विशेष प्रावधानों की उम्मीद

उद्यमियों ने सुरक्षा और ट्रैफिक समस्याओं के बारे थाना प्रभारी को करवाया अवगत

गुड़गांव | फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुरुग्राम द्वारा सेक्टर-37 के उद्यमियों की एक महत्वपूर्ण की गई, जिसमें मुख्य रूप से सेक्टर-10ए के थाना प्रभारी नवीन कौशिक दलबल के साथ उपस्थित हुए। मीटिंग के दौरान सेक्टर-37 और आस-पास के एरिया में लॉ एंड आर्डर की समीक्षा की गई और विस्तार से एरिया की सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। उपस्थित उद्यमियों ने उनके समक्ष सेक्टर में सुरक्षा और ट्रैफिक संबंधी समस्याओं के बारे उन्हें अवगत करवाया। थाना प्रभारी कौशिक ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस मीटिंग में फेडरेशन के प्रांत महासचिव दीपक मैनी, गुरुग्राम के प्रधान पीके गुप्ता, उप प्रधान रवीन जैन, महासचिव डॉ. एसपी अग्रवाल सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर नई दिल्ली 24-01-2022

पंजाब केसरी MON,24 JANUARY 2022
EDITION: GURGAON KESARI, PAGE NO. 4

एफआईआई की आयोजित हुई बैठक

बैठक में सेक्टर-10 प्रभारी को सम्मानित करते हुए

बैठक में क्षेत्र के लॉ एंड आर्डर की समीक्षा की गई

गुड़गांव, 23 जनवरी (ब्यूरो): उद्योगों के वेलफेयर के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का सेक्टर-37 में उद्योगपतियों की एक बैठक आयोजित हुई। जिसमें जिले व दूर दराज से आए उद्यमियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से सेक्टर-10 के थाना प्रभारी नवीन कौशिक भी अपनी टीम के साथ शामिल हुए। बैठक में सेक्टर-37 के आसपास के लॉ एंड आर्डर की समीक्षा की गई। बैठक में उद्यमियों ने क्षेत्र की सुरक्षा व ट्रैफिक संबंधी समस्याओं के बारे उन्हें अवगत करवाया। थाना प्रभारी नवीन कौशिक ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आश्वासन दिया कि उनके एरिया में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नही दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रांत महासचिव दीपक मैनी, गुरुग्राम के प्रधान पीके गुप्ता, उप प्रधान रवीन जैन, महासचिव डॉ एसपी अग्रवाल, सहसचिव सौरभ जुनेजा, लेबर लॉ एडवाइजर आरएल शर्मा, कार्यकारणी सदस्य अमन गुप्ता, राजेंद्र सैनी व संत राम शमा मौजूद रहे। इसके अलावा उद्योगपति डॉ. केके अग्रवाल, विनोद गुप्ता, नवनीत गोयल, पियूश गुप्ता, संजीव मैनी, इन्द्र जीत सिंह, सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग व उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी उद्योग हितों के लिए लोगों के बीच सुझाव रखे।

क्षेत्र की समस्याओं को लेकर थाना प्रभारी के साथ एफआईआई ने की बैठक

बैठक में शामिल उद्यमी व थाना प्रभारी।

गुरुग्राम, बुलंद खोज/लोकेश कुमार। उद्यमियों के हितों के लिए कार्यरत फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआईआई) द्वारा सेक्टर 37 के उद्यमियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सेक्टर 10ए थाना प्रभारी नवीन कौशिक शामिल हुए।

बैठक में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की गईऔर विस्तार से एरिया की सुरक्षा संबंधी विषयों पर भी बल दिया गया। संस्था के प्रांत महासचिव दीपक मैनी ने बताया कि उद्यमियों ने सेक्टर में सुरक्षा और ट्रैफिक संबंधी समस्याओं बारे उन्हें अवगत कराया। थाना प्रभारी ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए और आश्वस्त किया कि उनके एरिया में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नही दिया जाएगा।

बैठक में पीके गुप्ता, रवीन जैन, डा. एसपी अग्रवाल, मनोज गर्ग, सौरभ जुनेजा, आरएल शर्मा, अमन गुप्ता, राजेंद्र सैनी, संत राम शर्मा, डॉ. केके अग्रवाल, विनोद गुप्ता, नवनीत गोयल आदि मौजूद रहे।

बायो-टेक्नोलाजिकल इंडस्ट्री को लेकर बजट में हो खास बात

बजट 2022-23 बिगुल

एफआइआइ के महानिदेशक दीपक जैन।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: आम बजट 2022-23 को लेकर फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआइआइ) द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विभिन्न क्षेत्रों की बेहतरी के लिए सुझाव भेजे गए हैं। इसमें मुख्य रूप से बायो-टेक्नोलाजिकल इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की मांग की गई है।

एफआइआइ के महानिदेशक दीपक जैन ने बताया कि एक फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले आम बजट को लेकर जो सुझाव दिए हैं वह काफी महत्वपूर्ण हैं। यदि उन्हें बजट में शामिल किया गया तो यह देश के आर्थिक विकास में विशेष मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि बायो-टेक्नोलाजिकल इंडस्ट्री देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) को तेजी से बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है।

इस क्षेत्र की बात की जाए तो बायो टेक्नोलाजी एक उभरता हुआ मजबूत आर्थिक स्तंभ है। वर्ष 2025 तक इस क्षेत्र का कारोबार 150 बिलियन डालर के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डालर की बनाने की क्षमता निहित है। जरूरत है इसे जमीनी स्तर पर प्रोत्साहित करने की। अभी देश में इसकी कुल क्षमता का केवल दो प्रतिशत ही इस्तेमाल हो पा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले आम बजट 2022-23 में इस क्षेत्र से संबंधित विशेष घोषणा की जाएगी।

एफआइआइ के सुझाव पत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार को लेकर कदम उठाने की जरूरत है। वर्तमान में देश की जीडीपी का केवल 1.4 प्रतिशत आवंटन ही स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है। शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो कौशल विकास को लेकर और मजबूती प्रदान करने के लिए बजट में प्रविधान होना चाहिए।

आटोमोबाइल क्षेत्र को लेकर सुझाव दिया गया है कि कच्चे माल की बढ़ती कीमत के कारण यह क्षेत्र काफी परेशान है। वहीं सेमीकंडक्टर का अभाव भी आटोमोबाइल क्षेत्र को पीछे धकेलने वाला साबित हो रहा है। इसे लेकर नीति निर्माताओं को तुरंत सावधान होने की जरूरत है। सरकार को संकट काल में सब्सिडी देनी चाहिए। वैश्विक व्यापार के मद्देनजर भी विशेष ध्यान देने चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री को यह सुझाव भी दिए

निर्यातक को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) से प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इसमें काफी समय लगता है। इसका सरलीकरण किया जाए। 427 से अधिक एसाइजेड को मंजूरी देने के बाद भी वर्तमान में 297 एसाइजेड चालू है। एमएसएमई प्रोत्साहन के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं।

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स योजना को लेकर दो साल का मानदंड
- स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी और डीप साइंस क्षेत्र के अनुकूल नहीं है। इसे अनुकूल बनाने पर हो जोर।
- एंजेल इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने को लेकर इसे कर मुक्त किया जाए।

FII IN MEDIA

बातचीत | सेक्टर-37 औद्योगिक क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को लेकर भी हुई बात, ला एंड आर्डर को लेकर बैठक में की गई समीक्षा

सुरक्षा पर बैठक में थाना प्रभारी और उद्यमियों में चर्चा

सेक्टर-37 औद्योगिक क्षेत्र में चौकसी रखते हुई बैठक में सेक्टर दस थाना प्रभारी नवीन कौशिक के साथ सुरक्षा गार्ड आदि के... फोटो : जागरण

वर्षीय महिला की मृत्यु हुई है। महिला | सोमवार को संक्रमण दर 21.26 दर्ज | चुके हैं। 39,698 म हुए। 20 मरीजों की म

आइटीसीसी और एफआइआइ में करार

जासं, गुरुग्राम: भारत-थाई चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आइटीसीसी) और फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआइआइ) के बीच औद्योगिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया गया। करार थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में मंगलवार को किया गया। इस बात की जानकारी एफआइआइ के महानिदेशक दीपक जैन ने दी। उन्होंने बताया कि एफआइआइ थाईलैंड चैप्टर की ओर से चेयरमैन राजेंद्र खिमसेरा और आइटीसीसी की तरफ से अध्यक्ष रवि सिंघल ने करार पर हस्ताक्षर किया। दीपक जैन का कहना है कि भारत और थाईलैंड अंडमान सागर में सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हैं। पिछले लगभग 20 साल में नियमित राजनीतिक आदान-प्रदान, बढ़ते व्यापार और निवेश के साथ, थाईलैंड और भारत के बीच लुक वेस्ट और एक्ट ईस्ट की रणनीति व्यापक साझेदारी के रूप में विकसित हुई है। दीपक जैन ने कहा कि एफआइआइ एक गैर-लाभकारी संगठन और सरकार और उद्योगों के बीच सलाहकार का काम करती है।

सुरक्षा कारण से 26 को ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

We are taking all necessary CO

BLAZE

फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा श्रमिकों के लिए एक और मेगा वैक्सीनेशन कैम्प आयोजित

ब्यूरो/गुड़गांव मेल

गुड़गांव, 20 जनवरी। आज फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा मनोज गर्ग के उधोगिक प्रतिष्ठान लीन डिजाइन कंपनी, प्लॉट नम. 366 सेक्टर 37, गुरुग्राम में श्रमिकों के लिए एक और मेगा वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमे लगभग 262 श्रमिकों को कॉविशिल्ड वैक्सीन लगाई गई, वैक्सिनेशन कैम्प का शुभारंभ सेक्टर 37 के एसएचओ श्री सुरेश चंद के करकमलों द्वारा किया गया, एसएचओ श्री सुरेश चंद ने अपने वक्तव्य में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की सराहना करते हुए कहा की इस तरह के कैंप्स के आयोजन हर संस्था को आगे बढ़ कर करना चाहिए तभी इस महामारी से निजात पाई जा सकती है । उन्होंने कहा की एफआईआई वैक्सिनेशन कैंप्स के अलावा भी उद्योगिक इकाइयों और श्रमिकों के लिए जितने लगन और से कार्य कर रही है इसके लिए एफआईआई की पूरी टीम बधाई की पात्र है और कहा की कॉविड के केस काफी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, श्रमिकों और प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य व उनकी इम्यूनिटी का विशेष ध्यान रखने की अवश्यकता है, उन्होंने कहा की औद्योगिक परिसर में सभी लोग प्रॉपर मास्क लगा कर रखें परिसर में बाहर से आने वाले सभी विजिटर्स का टेंपरेचर भी अवश्य चेक करें । जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है व उन्हे कौशिश करके वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए व आज के कैंप में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रांत महासचिव दीपक मैनी गुरुग्राम के प्रधान पी. के. गुप्ता, उप प्रधान रवीन जैन, महासचिव डॉ. एस. पी. अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डी. पी. गौड़, सह सचिव सौरभ जुनेजा, कार्यकारणी सदस्य अमन गुप्ता, लेबर लॉ एडवाइजर आर. एल. शर्मा, उद्योगपति श्री मनोज गर्ग, पीयूष वर्मा एवं भारत कुमार आदि ने कैम्प में अपना कीमती समय देकर इस यज्ञ में अपनी आहुत देने का कार्य किया ।

पंजाब केसरी | MON,24 JANUARY 2022 EDITION: GURGAON KESARI, PAGE NO. 3

भारत व थाईलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करते दोनों देशों के प्रतिनिधि।

गुड़गांव, 23 जनवरी (ब्यूरो): भारत थाई चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईटीसीसी) व फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआईआई) ने 18 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। ताकि दोनों संगठनों के बीच औद्योगिक व शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके। ज्ञात हो कि भारत व थाईलैंड अंडमान सागर में सीमा साझा करने वाले विश्वासपात्र पड़ोसी हैं।थाईलैंड के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्कों और लोगों से लोगों के बीच व्यापक संपर्कों के इतिहास में निहित हैं।इसके अलावा बौद्ध धर्म की कड़ी भारत में बौद्ध रुचि के स्थानों के लिए नियमित तीर्थ यात्राओं में परिलक्षित होती है। इसी तरह थाई वास्तुकला, मूर्तिकला, नृत्य, नाटक व साहित्य में परिलक्षित होने वाले हिंदू पाए जा सकते हैं। इस अवसर पर दीपक जैन महानिदेशक (एफआईआई) ने बताया कि पिछले दो दशकों में नियमित राजनीतिक आदान-प्रदान बढ़ते व्यापार और निवेश के साथ,थाईलैंड और भारत के बीच लुक वेस्ट व एक्ट ईस्ट की रणनीति एक व्यापक साझेदारी के रूप में विकसित हुई है। कार्यक्रम सम्पादन पर दीपक जैन ने कहा हम बहुत आशावादी व आश्वस्त हैं कि यह समझौता आने वाले दिनों में दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार के अवसरों के विस्तार, बौद्धिक संपदा, व्यापार व पर्यटन में घातीय वृद्धि को मजबूती बढ़ाएगें।

आइटीसीसी और एफआइआइ में करार

जासं, गुरुग्राम: भारत-थाई चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (आइटीसीसी) और फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआइआइ) के बीच औद्योगिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया गया। करार थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में मंगलवार को किया गया। इस बात की जानकारी एफआइआइ के महानिदेशक दीपक जैन ने दी। उन्होंने बताया कि एफआइआइ थाईलैंड चैप्टर की ओर से चेयरमैन राजेंद्र खिमसेरा और आइटीसीसी की तरफ से अध्यक्ष रवि सिंघल ने करार पर हस्ताक्षर किया। दीपक जैन का कहना है कि भारत और थाईलैंड अंडमान सागर में सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हैं। पिछले लगभग 20 साल में नियमित राजनीतिक आदान-प्रदान, बढ़ते व्यापार और निवेश के साथ, थाईलैंड और भारत के बीच लुक वेस्ट और एक्ट ईस्ट की रणनीति एक व्यापक साझेदारी के रूप में विकसित हुई है। दीपक जैन ने कहा कि एफआइआइ एक गैर-लाभकारी संगठन और सरकार और उद्योगों के बीच एक सलाहकार का काम करती है।

50 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन शुल्क हो निशुल्क: चिरंजीव ठाकुर

सूक्ष्म, कुटीर एवं लघु उद्योगों का सरकार आधा करे बिजली का बिल-फेडरेशन

- प्रदेश के 40 हजार लघु उद्यमियों को मिलेगी राहत
- लघु उद्योगों को 100 किलो वाट तक हो घरेलू दरें लागू

अर्थ प्रकाश/राजेंद्र

मानपुरा, 30 जनवरी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घरेलु कनेक्शनों पर 60 यूनिट तक बिजली निशुल्क करने के सरकार के फैसले का फेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री ने स्वागत करते हुए कहा की इस तरह के फैसले से गाव एव गरीब लोगों को राहत की सास मिलेगी। वही फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीव ठाकुर ने कहा की सरकार को कुटीर, सूक्ष्म एव लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 50 किलो वाट तक बिजली की दरें आधी करनी चाहिए। 50 से 100 किलो वाट लोड तक घरेलु दर से बिजली देनी चाहिये जिससे कुटीर, सूक्ष्म एम लघु उद्योगों को राहत मिल सके। उन्होने कहा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो प्रदेश के अलग अलग कोनें में बसे 40 हजार घरेलु, कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा और यह प्रदेश सरकार का एक एतिहासिक निर्णय तो होगा ही साथ मे सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले लघु उद्योगों के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष उमाशंकर खोकर व प्रदेश सचिव अनिल मलिक ने कहा की हिमाचल बिजली उत्पाद का सबसे बड़ा राज्य है,इसलिए प्रदेश सरकार को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिये बडी रियायत देनी चाहिए। फार्मा विंग प्रमुख हिमाचल प्रदेश मृणाल खटव ने कहा कि नए एव सूक्ष्म उद्योगों को निवेश के लिये हिमाचल सरकार को 100 किलो वाट तक के कनेक्शन निशुल्क करने चाहिए ताकी नये निवेश को बढ़ावा मिल सके। राज्य महासचिव राम कृष्ण शर्मा एवं सह सचिव देवेन्द्र राणा ने कहा की भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का 80 फीसदी भागीदारी है,इसलिए सरकार को इनके बेहतरी के लिये उचित कदम उठने चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ठाकुर ने कहा की इस संदर्भ में जल्दी ही फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमण्डल मुख्यमंत्री,उद्योग मंत्री एवं उर्जा मंत्री से मुलाकात करेंगे।

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII IN MEDIA

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भी विद्युत बिल में राहत दे सरकार

संवाद सहयोगी, कुल्लू : हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की 60 यूनिट तक बिजली निशुल्क करने के फैसले का फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है। फेडरेशन ने कहा है कि इस फैसले से गरीब लोगों को राहत मिलेगी। वहां जारी बयान में फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीव ठाकुर ने कहा कि सरकार को कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50 किलोवाट तक बिजली की दर आधी करनी चाहिए। 50 से 100 किलोवाट लोड तक घरेलू दर से बिजली देनी चाहिए, जिससे कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को राहत मिल सके।

चिरंजीव सिंह ठाकुर ● सौ. ह्यंप

उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो प्रदेश में स्थापित 40 हजार घरेलू, कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा। यह प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय तो होगा ही साथ में सर्वाधिक रोजगार देने वाले लघु उद्योगों के विकास में भी यह मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष योगराज छोकर व प्रदेश सचिव अनिल मलिक ने कहा कि हिमाचल बड़ा बिजली उत्पाद राज्य है, इसलिए प्रदेश सरकार को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बड़ी रियायत देनी चाहिए।

फार्मा विंग प्रमुख मृणाल यादव ने कहा कि नए एवं सूक्ष्म उद्योगों को निवेश के लिए हिमाचल सरकार को 100 किलोवाट तक के कनेक्शन निशुल्क करने चाहिए। राज्य महासचिव रामकृष्ण शर्मा एवं सह सचिव देवेंद्र राणा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की 80 फीसद भागीदारी है, इसलिए सरकार को उनके बेहतरी के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। चिरंजीव ठाकुर ने कहा कि इस संदर्भ में जल्दी ही फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करेगा।

भारत-थाई चैंबर ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक समझौता ज्ञापन किया

'इस बार ऐसा हो बजट, जिससे हो हमारे रुपये की बचत'

आज पेश होने वाले बजट से उद्यमियों को GST की दरों में कमी की आस, महिलाएं चाहती हैं महंगाई पर लगाम

हर सेक्टर को निर्मला के आम बजट से खास सौगात की आस

कानून पर रोक लगने से उद्योग जगत खुश

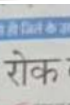

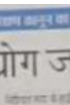

दैनिक भास्कर — नई दिल्ली 04-02-2022

निजी उद्योगों में 75% आरक्षण पर रोक का औद्योगिक संगठनों ने किया स्वागत

उद्योग जगत के लिए यह बहुत ही अच्छा फैसला

हरियाणा वासियों को केंद्रीय बजट से उम्मीदें

उद्योगपतियों को ऋण देते समय भेदभाव नहीं होना चाहिए

3 वर्ष से उद्योगपतियों की हालत पतली, सरकार करें मदद

गणेश सिंह चौहान
patrika.com

चंडीगढ़. केंद्रीय मंत्री सीतारमण के बजट पर हरियाणा के व्यापारी और उद्योगपतियों की नजर है। दउद्योगपतियों को खासकर केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें है क्योंकि पिछले 3 वर्ष से कोरोनावायरस के चलते हरियाणा प्रदेश के उद्योगों की हालत पतली है।

एफआईआई के सीएसआर कमेटी के चेयरमैन सरदार हरभजन सिंह का कहना है केंद्र बजट में उद्योगों के लिए विशेष योजना के तहत प्रावधान करें, जिससे उद्योगपति उबर सके और जो उद्योग बंद होने के कगार पर हैं वह पहले की तर्ज पर चल सकें।

गुरुग्राम सेक्टर 37 औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के.के. गांधी का कहना है सबसे बड़ी बजट से उम्मीद तो यह रहती है कि जो साल भर में कम आ रहा है उसमें से भविष्य के लिए सलीके से बचत हो जाए और टैक्स आदि के रूप में कमाई का बड़ा हिस्सा ना देना पड़े। इनकम टैक्स स्लैब का दायरा 700000 किया जाए।

मानेसर औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष पवन यादव का कहना है उद्योगपति उद्योगों को चलाने के लिए बैंक से कर्जा लेता है, उसके साथ ब्याज दर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। रेवाड़ी बावल के उद्योगपति मुख के यादव का कहना है मिनी उद्योग के लिए केंद्र और राज्य सरकार को अलग से बजट में प्रावधान करना चाहिए जिससे हरियाणा में और उद्योग स्थापित हो सके।

लेबर एडवोकेट एलएन शर्मा का कहना है उद्योग जब बढ़ेंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा हरियाणा सरकार ने 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार का कानून तो बना दिया लेकिन उद्योगों के लिए खास योजनाएं नहीं बनाई अगर उद्योग नहीं स्थापित होंगे तो 75% स्थानीय युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा यह अभी चर्चा का विषय बना हुआ है।

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII IN MEDIA

High Court stays Haryana job quota for locals

Deepak Maini, secretary-general, Federation of Indian Industry, Haryana Chapter, hailed the stay order as "good news for the world of business".

"The FII welcomes the order of the Punjab and Haryana High Court and expresses its gratitude. Jobs in private sector should only be granted only on the basis of merit," said Mr. Maini.

Indian Staffing Federation (ISF), a representative voice to the Indian staffing industry with over a hundred organised staffing companies employing around one million contract workers across India, also welcomed the decision.

"The court order will allow Haryana Government to reconsider the appeal from industries and companies to scale up the skills of youth, infrastructure and economic development, which would create sustainable and long-term employment opportunities within the state. Legislations like the Haryana State Employment of Local Candidates Act are unnecessary barriers, which impact both economic and employment growth in the state," said Lohit Bhatia, president, ISF.

Mr. Chautala said the government would analyse the court order along with the legal experts and take the next legal step to ensure the implementation of the law.

HC stays Haryana job quota for locals

Industry bodies welcome order; Govt. vows to ensure local employment

ASHOK KUMAR
GURUGRAM

The Punjab and Haryana High Court on Thursday granted an interim stay on the controversial law for reservation of 75% jobs in private companies, societies and trusts for local Haryana candidates.

While several industrial associations welcomed the order, Deputy Chief Minister Dushyant Chautala tweeted that the government would continue to fight for employment opportunities for the local youth.

The matter came up for hearing before the division bench of Justices Ajay Tiwari and Pankaj Jain with the petitioners seeking an interim stay on the law that came into force on January 15. The hearing on the matter slated for January 12 earlier was adjourned due to COVID-induced restrictions.

> We will continue to fight for employment opportunities of Haryanvi youth
>
> DUSHYANT CHAUTALA
> Haryana Deputy Chief Minister

Advocate Tushar Sharma, representing Manesar Industries Welfare Association, one of the petitioners, said the court, granting the interim stay, put only one question to the State as to how they could grant reservation in employment on the basis of a domicile as it violated Article 16 of the Constitution.

Around eight petitioners, including different industrial associations and individuals, moved the court last December against the law, pleading that it was against the provisions of the Constitution and the basic principle of meritocracy that acted as the foundation for businesses to grow and remain competitive. The court had then issued notice to the government seeking a reply.

CONTINUED ON ▸ PAGE 8

फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ विशेष बैठक का आयोजन

गुरुग्राम, 31 जनवरी (रैपको न्यूज)। उद्योगो के वेलफेयर के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुरुग्राम द्वारा सेक्टर 37 के उद्योगपतियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग सेक्टर 37 में की, जिसमें गणमान्य उद्यमियों ने भाग लिया। मीटिंग में मुख्य रूप से सेक्टर 10 ऐ के थाना प्रभारी नवीन कौशिक जी भी दलबल के साथ उपस्थित हुए। मीटिंग के दौरान सेक्टर 37 और आसपास के एरिया में लॉ एंड आर्डर की समीक्षा की गई और विस्तार से एरिया की सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा की गई।उपस्थित उद्यमियों ने उनके समक्ष सेक्टर में सुरक्षा और ट्रैफिक संबंधी समस्याओं बारे उन्हें अवगत करवाया, थाना प्रभारी नवीन कौशिक जी ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए और आश्वासन दिया कि उनके एरिया में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नही दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रांत महासचिव दीपक मैनी, गुरुग्राम के प्रधान पी.के. गुप्ता, उप प्रधान रवीन जैन, महासचिव डॉ एस. पी. अग्रवाल, सहसचिव सौरभ जुनेजा, लेबर लॉ एडवाइजर आर.एल. शर्मा, कार्यकारणी सदस्य अमन गुप्ता, राजेंद्र सैनी तथा संत राम शर्मा, सम्मानित उद्योगपति डॉ. के. के. अग्रवाल, विनोद गुप्ता, नवनीत गोयल, पयूश गुप्ता, संजीव मैनी, इन्द्र जीत सिंह, राजेश गुप्ता, एल. एन. छाबड़ा, सुशील मैनी, मनोज गर्ग, मो. हारून, हंसराज मकड़, डॉ. पंकज अग्रवाल, राकेश शर्मा, सुमित जैन एवं डॉ. विभव ने शिरकत की तथा अपने विचार और सुझाव दिए।

कोविड महामारी के पश्चात विश्व की फार्मेसी बनकर उभरा भारत

देवभूमि मिरर/बद्दी

फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (एफएफ आई) व लघु उद्योग भारती के हिमाचल प्रदेश यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारी व कोरटेक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित सिंगला ने आज केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किये केंद्रीय बजट भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान देश का प्रत्येक वर्ग प्रभावित हुआ जिसमें लघु, मध्यम उद्योग और फार्मा उद्योग को कड़ा संघर्ष करना पड़ा. केंद्रीय सरकार ने इस मुश्किल की घड़ी में इन उद्योगों को कर्ज प्रदान कर राहत प्रदान की यही कारण रहा कि यह उद्योग सेवायें प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार की मदद के कारण ही संभव हुआ कि भारत का फार्मा उद्योग विश्व भर में तीसरे स्थान पर आ गया है. कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार की नीतियों के कारण जहाँ भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाने लगा वहीं सरकार के टीकाकरण अभियान की उपलब्धि है कि देश में कोविड महामारी उतनी जानलेवा नहीं हुई जितनी विदेश में रही. टीकाकरण के कारण देश में कोविड एक फ्लू मात्र हो पाया है. सुमित सिंगला ने केंद्रीय बजट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2022 के यूनियन बजट में सरकार ने विदेशों पर भारतीय फार्मा उद्योग की 80 से 100 प्रतिशत निर्भरता को भांपते हुए एक हाई लेवल समिति का गठन कर उसके सुझावों को जिसमें क्रिटिकल बल्क ड्रग्स के देश के भीतर ही निर्माण को उत्साहित करने पर बल दिया गया है. इसके लिए बजट में प्रमोशन लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम को लागू किया गया है जिसके अधीन बायो फार्मास्युटिकल्स, ए पी आई, के एस एम ड्रग्स व इंटर मेडिएट (तीन श्रेणियाँ) मेडिकल मशीनरी पर देश के भीतर निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु 3420 करोड़ की योजना रखी है जोकि 6 वर्षों के निर्माण में बढ़ोतरी को देखते हुए उद्योग को इंसेंटिव के रूप में प्रदान की जाएगी. इस योजना में क्रिटिकल ए पी आई, का निर्माण देश के भीतर करने हेतु अलग से 6940 करोड़ रुपए आगामी 8 वर्षों में आरक्षित हैं. यह योजना देश के 13 सेक्टर में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भारतीय उद्योग को केंद्रीय सरकार का समर्थन देने हेतु आरक्षित किए गए 1.97 लाख करोड़ रुपए के अंतर्गत किये गए हैं. सुमित सिंगला ने कहा कि भारत सरकार की नीतियों के कारण भारतीय फार्मा उद्योग विश्व में तीसरे स्थान पर आ पहुंचा है जो कि 24.4 यू एस बिलियन डॉलर का स्तर पार कर चुका है जिसका विश्व भर के फार्मा उद्योग में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हो गयी है।

Sumit Singla hails relief for pharma industry in Budget

ANWAR HUSSAIN
NALAGARH, FEB 1

Sumit Singla, a senior official of the Himachal Pradesh unit of Federation of Indian Industries (FII) and Laghu Udyog Bharati and managing director of Cortech Group, while praising the central budget presented by the central government today said that during the Covid epidemic, as every section of the country was affected, small and medium industry and pharma industry had to fight hard. The central government provided relief to these industries in these difficult times by providing loans, which is the reason why these industries are providing services. He said that it was only due to the help of the central government that India's pharma industry came third in the world.

Due to the policies of the Indian government during the Corona epidemic, while India came to be called the pharmacy of the world, the achievement of the government's vaccination campaign is that the Covid epidemic was not as deadly in the country as it was abroad. Due to vaccination, Covid has become a flu in the country. Highlighting the Union Budget, Sumit Singla said that in the Union Budget 2022, the government, realizing the 80 to 100 per cent dependence of the Indian pharma industry on foreign countries, constituted a high-level committee to look into its suggestions including critical bulk drugs within the country. The emphasis is on encouraging construction. To this end, Promotion Linked Incentive System has been implemented in the budget under which a plan of Rs 3420 crore has been made, which will be provided as an incentive to the industry in view of the increase in construction over 6 years. In the scheme, Rs 6940 crore has been reserved separately for construction of critical API within the country in next 8 years. These schemes have been undertaken under Rs 1.97 lakh crore reserved to support Indian industry in the global competition in 13 sectors of the country.

WED 02 FEBRUARY 2022
EDITION GURGAON KESARI, PAGE NO. 4

बजट वैक्सीन से उद्योगों में रिकवरी की उम्मीद

बजट में भविष्य की झलक

उद्योग संघों की राय

केंद्रीय बजट को किसी उद्यमी ने उद्योग जगत के हित में बताया है तो कुछ ने कहा कि लघु उद्योगों के लिए कोई खास रुचि नहीं है। वहीं कुछ ने कहा कि इसमें भविष्य के भारत की झलक दिखती है। हिमाचल के अलग-अलग उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट पर विभिन्न प्रतिक्रिया दी है।

फार्मा सेक्टर के लिए केंद्रीय बजट मिला जुला है और इसमें एमएसएमई को तरजीह दी गई है। कस्टम ड्यूटी कम करने का स्वागत करता हूं। नए उद्यम को 15 प्रतिशत इनकम टैक्स की छूट एक वर्ष तक बढ़ाना सराहनीय है।

-डा. राजेश गुप्ता, ...

बजट में सरकार ने फार्मा कंपनियों की विदेशों पर निर्भरता को कम करने का प्रयास किया है। क्रिटिकल बल्क ड्रग्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमोशन लिंक इंसेंटिव सिस्टम लागू किया है।

-सुमित सिंगला, वरिष्ठ पदाधिकारी, फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज एवं लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश।

केंद्रीय बजट से कोरोना काल में नुकसान झेल रहे उद्योगों को संजीवनी मिलेगी। लाजिस्टिक सेंटर विकसित होने से उद्योगों में तैयार माल एक से दूसरी जगह भेजना आसान व सुरक्षित रहेगा।

बजट घरेलू, कुटीर, सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए निराशा लेकर आया है। एमएसएमई सेक्टर के उद्योगों के उत्थान के लिए भी प्रावधान नहीं हुआ है। मध्यम वर्गीय लोगों व व्यापारियों को बजट ने निराश किया है।

लघु उद्योग देश में 80 प्रतिशत रोजगार सृजित करते हैं लेकिन कोई प्रावधान न होना केंद्र सरकार की उपेक्षा को दर्शाता है। अगर सरकार चाहती तो लघु उद्योगों की ऋण की सीमा बढ़ाती और ब्याज दरों में कमी करती।

-अशोक राणा, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती ...

केंद्रीय वित्त मंत्री ने विकास-उन्मुख, विस्तारवादी बजट पेश किया है। बजट पोषण में मदद करेगा और आर्थिक विकास का समर्थन करेगा।

आयकर छूट न बढ़ने से निराशा हाथ लगी। एमएसएमई सेक्टर में बिना गारंटी के ऋण की सीमा बढ़ाई गई है उसका स्वागत है। सरकार को माता व पैकिंग उद्योग के लिए नीति बनानी चाहिए थी।

लौह उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए थे क्योंकि इसका देश के विकास में अहम योगदान है। बिजली संचालित वाहनों की बैटरी बदलने की नीति बनाने का सराहनीय है।

किसानों से जुड़े टैक्सटाइल सेक्टर को खास नहीं मिला है। टैक्सटाइल सेक्टर सर्वाधिक रोजगार देता है।

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII IN MEDIA

टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे गुड़गांव के लोग

प्रमुख संवाददाता, गुड़गांव

यहां के लोग टैक्स स्लैब मे बदलाव की उम्मीद कर रहे थे पर ऐसा न होने से उन्हें निराश हुई। गुड़गांव के लाखों करदाताओं को इसका लाभ नहीं मिला। हालांकि कृषि व बागवानी को प्रोत्साहित किए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी इनेबल डिवलेपमेंट पर जोर दिया गया है। जिसका लाभ कहीं न कहीं जिले को भी मिलने की उम्मीद है। बजट पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया रही।

फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने भी बजट पर रखी निगाहें

भविष्योन्मुखी बजट, मगर इंडस्ट्री को मिला उम्मीद से काफी कम

आम बजट को लेकर साइबर सिटी के उद्यमियों की रही मिलीजुली प्रतिक्रिया

भारत-थाई चैंबर आफ कामर्स और एफआईआई के बीच एमओयू, दोनों संगठनों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का प्रस्ताव

फरीदाबाद, 31 जनवरी (रैपको न्यूज)। भारत और थाईलैंड अंडमान सागर में सीमा साझा करने वाले विस्तारित पड़ोसी हैं। थाईलैंड के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध पुराने सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों और लोगों से लोगों के बीच व्यापक संपर्कों के इतिहास में निहित हैं। इसके अलावा, बौद्ध धर्म की काफी भारत में बौद्ध रुचि के स्थानों के लिए नियमित तीर्थयात्राओं में परिलक्षित होती है और इसी तरह थाई वास्तुकला, कला, मूर्तिकला, नृत्य, नाटक और साहित्य में परिलक्षित होने वाले हिंदू तत्व पाए जा सकते हैं।

इस अवसर पर दीपक जैन, महानिदेशक, एफआईआई ने बताया कि पिछले दो दशकों में नियमित राजनीतिक आदान-प्रदान, बढ़ते व्यापार और निवेश के साथ, थाईलैंड और भारत के बीच क्रमशः लुक वेस्ट और एक्ट ईस्ट की रणनीति एक व्यापक साझेदारी के रूप में विकसित हुई है।

उल्लेखनीय है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआईआई), एक गैर-लाभकारी संगठन और सरकार और उद्योगों के बीच एक सलाहकार इंटरफ़ेस है, जिसका गठन भारतीय उद्यमियों, विदेशी निवेशकों और सरकार को एक संरचित और व्यापक सलाह और समर्थन इंटरफेस प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। एफआईआई ने दोनों देशों के बीच इस संबंध को मजबूत करने और दोनों देशों में व्यापार जगत के नेताओं के लिए अधिक अवसर पैदा करने के अपने निरंतर प्रयास में भारत-थाई चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एफआईआई के महानिदेशक दीपक जैन ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी, आकर्षक बुनियादी ढांचे के बाजार, और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक प्रभाव के साथ भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में थाईलैंड को पेश करने की असीम संभावनाएं हैं। वास्तव में, थाईलैंड में भारत में निवेश करके, मेक इन इंडिया बाय थाईलैंड फॉर इंडियंस एंड द वर्ल्ड, और थाईलैंड में विस्तार करने वाले भारतीय उद्यमों में निवेश करके आत्मनिर्भर भारत में आपूर्ति श्रृंखला अंतराल को भरने में दोनों तरह से अवसर हैं।

समापन पर, दीपक जैन ने कहा कि हम बहुत आशावादी और आश्वस्त हैं कि यह समझौता आने वाले दिनों में दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार के अवसरों के विस्तार, बौद्धिक संपदा, व्यापार और पर्यटन में घातीय वृद्धि को मजबूत और बढ़ाएगी।

पुरानी स्कीमों की अवधि बढ़ाने का स्वागत बल्क ड्रग पार्क की घोषणा न होने से मायूस

बद्दी (सोलन)। फार्मा सेक्टर के लिए बजट मिला-जुला रहा है। एमएसएमई को तरजीह दी गई है। पुरानी स्कीमों की अवधि बढ़ाकर उद्योगपतियों को राहत दी गई है, लेकिन हिमाचल में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब होने के बावजूद फार्मा संचालकों को निराशा हाथ लगी है। पहाड़ी राज्यों के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम 2022 में समाप्त हो रही है, इसे नहीं बढ़ाया गया। बल्क ड्रग फार्मा पार्क की ऊना के लिए घोषणा भी नहीं की गई है। संवाद

फार्मा

उद्योग लगाने पर आयकर में छूट सराहनीय

एचपीएमए के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की अवधि बढ़ाने, कुछ केमिकल के आयात पर कस्टम ड्यूटी कम करने, दो वर्ष के दौरान इकम टैक्स की रिटर्न में सुधार करने, नए उद्योग लगाने पर आयकर में छूट देना स्वागत योग्य है। लेकिन प्रदेश के दवा निर्माताओं को इन्वेस्टमेंट स्कीम की अवधि बढ़ाने व बल्क ड्रग पार्क ऊना के लिए घोषणा न करने पर मायूस होना पड़ा है।

मध्य वर्ग के लोग निराश

भारत उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष विरांजीव ठाकुर ने कहा कि मध्य वर्गीय लोगों को कर में कोई छूट नहीं दी गई है, जिससे लोगों को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए बजट में विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

फार्मा में कच्चे माल की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर नकेल कसे सरकार : सुमित सिंगला

आम लोगों के हित में है केंद्र सरकार का बजट

हिमाचल

दैनिक उत्तम हिन्दू 8

केंद्रीय बजट पर हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों रही मिली-जुली प्रतिक्रिया

बड़े उद्योगों ने भारत के भविष्य का बजट करार दिया, लघु उद्योगों को नहीं आया पसंद

बल्क ड्रग क्लस्टर तैयार होने से चीन पर निर्भरता होगी कम

फेडरेशन ऑफ इंडिया के हिमाचल इकाई के उपाध्यक्ष सुमित सिंगला ने कहा कि सरकार ने खाली जमीन पर क्लस्टर के रूप में बल्क पार्क खोलने की घोषणा से दवा निर्माताओं की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। 53 क्रिटिकल ड्रग तैयार करने के लिए छह हजार 190 करोड़ की घोषणा की गई है। यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा होगा। इससे भी चीन पर दवा निर्माताओं की निर्भरता कम होगी। कस्टम ड्यूटी कम करने से सामान के रेट कम होंगे, जिससे आम लोगों को फायदा होगा।

दवाओं को जीएसटी के एक स्लैब में नहीं रखा

दवा विक्रेता सचिन वैसल ने कहा कि बजट से दवा विक्रेताओं को निराश हाथ लगी है। सभी दवाइयों को एक स्लैब में पांच फीसदी जीएसटी लाने की उम्मीद थी लेकिन बजट में पचासक रखा गया। दवाइयों के लिए जीएसटी तीन प्रकार से लिया जाता है। जीवन रक्षक दवाइयों पर पांच फीसदी, सामान्य दवाइयों पर 12 तथा फूड सप्लीमेंट पर 18 फीसदी जीएसटी है। लेकिन हर दवाई जीवन रक्षक होती है इसलिए इसे पांच फीसदी वाले स्लैब में रखने की मांग की थी।

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII IN MEDIA

5:09 18%

The Korea Times

February. 9. 2022

Business 2022-02-09 12:09

FII, Eva Global Holdings aim to expand support for Korean companies in India

Mr. Deepak Jain
Director General – FII

Ms. Zena Chung
CEO -Eva Global Holdings

By Kim Hyun-bin

The Federation of Indian Industry (FII), a non-profit organization consisting of over 5,000 companies in India, and Eva Global Holdings, a consulting company operating in New York and Seoul, signed a memorandum of understanding (MOU) to help Korean businesses sell their products in India and search for newly emerging markets.

The MOU includes a wide scope of cooperation between the two organizations, seeking to promote trade and investment relations between the two countries.

The organizations will aid in trade and market research, conferences, symposiums and other methods of trade promotion activity in each country.

Both organizations will also organize B2B seminars, conferences, exhibitions, trade fairs and other promotional activities, while continuing to create and maintain exchanges of information about economic development and other matters for the business interests of their members.

Eva Global Holdings CEO Zena Chung won the Dr. Sarojini Naidu International award given by Asian Academy of Film and Television in India. She also received the "Pride of India" Award for her exemplary work in promoting India-Korea business ties in October 2021.
Chung also runs the Global Diplomats Forum to promote the economic and cultural development by utilizing incumbent and former high-ranking diplomats as board members.

Kim Hyun-bin
hyunbin@koreatimes.co.kr

एफआईआई और ईवा ग्लोबल होल्डिंग्स के मध्य हुआ एमओयू साईन

बिजली सिस्टम की कमजोरी से हो रहा उद्योगों को प्रोडक्शन लास

मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा को प्रमोट करे सरकार

नई राहें

- मार्केटिंग और इनवास्टमेन्ट्रफेसिंग यूनिटों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना लाकर
- देश-विदेश में बाजार तलाशने में भी छोटे उद्योगों को मिले सरकारी सहायता

ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए निगम बना रहा है दबाव

परेशानी

- उद्यमियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी राहत नहीं
- उद्यमियों की मांग, प्रदेश सरकार इस मामले में जल्द करे हस्तक्षेप

HARYANA

Air quality panel nod to run NCR industry on all 7 days

Commission had passed order to shut units for 2 days in week in region

TAKE TO PNG, BIOFUEL BY SEPT 30

Industries located in the NCR beyond the Government of National Capital Territory of Delhi should, under all circumstances, completely switch over to PNG or biomass fuels up to September 30, failing which such units will be shut. Commission for Air Quality Management

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII ACTIVITIES

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

CREATING OPPORTUNITIES...BUILDING NATION!!

Drone Formations at Rashtrapati Bhavan on eve of Republic Day

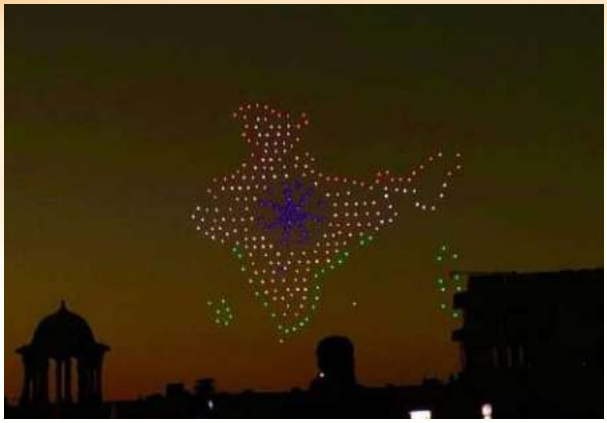

Rashtrapati Bhavan, India

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII ACTIVITIES

Subhash Chandra Bose Jayanti: PM Modi unveils Netaji's digital statue at India Gate, as Republic Day celebrations begin

India Gate, India

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII ACTIVITIES

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY
CREATING OPPORTUNITIES...BUILDING NATION!!

आज़ादी का अमृत महोत्सव

A glimpse of the iconic Nhat Tan bridge in Hanoi Vietnam lit in the Indian tricolour to mark the 73rd Republic Day of India. and other event in Hanoi Vietnam

Hanoi Vietnam

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII ACTIVITIES

FII Nigeria chapter represented by Kiran M Gosavi , President FII Nigeria , Shishir Verma, G S , FII Nigeria at the Ministry of Petroleum Resources.On behalf of FII Team we assured of our best support in getting Technology best suited to the CNG & LNG sector also assist Nigerian Gov on administration of CNG & LNG expansion programme. In the picture from left to right Dr. Ishaku Abner , Technical Advisor to Hon. Minister of State , Petroleum Resources, Kiran M Gosavi , President FII Nigeria, Dr. Mohammed M. Ibrahim , Chairman , National Gas Expansion Programme, Shishir Verma , Gen Secretary , FII Nigeria, David , PA to Chairman NGEP.

The FII Germany Team with His Excellency Ambassador to Germany and other Embassy Senior staff

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII ACTIVITIES

उधोगो के वेलफेयर के लिए दिनांक: 21.01.2022 को फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुरुग्राम द्वारा सेक्टर 37 के उधोगपतियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग सेक्टर 37 में की, जिसमें गणमान्य उद्यमियों ने भाग लिया। मीटिंग में मुख्य रूप से सेक्टर 10 ऐ के थाना प्रभारी नवीन कौशिक जी भी दलबल के साथ उपस्थित हुए। मीटिंग के दौरान सेक्टर 37 ओर आसपास के एरिया में लॉ एंड आर्डर की समीक्षा की गई और विस्तार से एरिया की सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। उपस्थित उधमियों ने उनके समक्ष सेक्टर में सुरक्षा और ट्रैफिक संबंधी समस्याओं बारे उन्हें अवगत करवाया, थाना प्रभारी नवीन कौशिक जी ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए और आश्वासन दिया कि उनके एरिया में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नही दिया जाएगा । इस महत्वपूर्ण मीटिंग में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रांत महासचिव दीपक मैनी, गुरुग्राम के प्रधान पी.के. गुप्ता, उप प्रधान रवीन जैन, महासचिव डॉ एस. पी. अग्रवाल, सहसचिव सौरभ जुनेजा, लेबर लॉ एडवाइजर आर.एल. शर्मा, कार्यकारणी सदस्य अमन गुप्ता, राजेंद्र सैनी तथा संत राम शर्मा, सम्मानित उद्योगपति डॉ. के. के. अग्रवाल, विनोद गुप्ता, नवनीत गोयल, पयूश गुप्ता, संजीव मैनी, इन्द्र जीत सिंह, राजेश गुप्ता, एल. एन. छाबड़ा, सुशील मैनी, मनोज गर्ग, मो. हारून, हंसराज मक्कड़, डॉ. पंकज अग्रवाल, राकेश शर्मा, सुमित जैन एवं डॉ. विभव ने शिरकत की तथा अपने विचार और सुझाव दिए ।

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

LET'S JOIN HANDS.
FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY
YOU FOCUS ON YOUR CORE BUSINESS.
FII CSR PROJECTS :
• PUBLIC HEALTH
• WOMEN EMPOWERMENT
• ROAD SAFETY
• SPORTS
• SKILL DEVELOPMENT
LET FII BE YOUR CSR PARTNER.
• REGISTERED UNDER SECTION 80G
• REGISTERED UNDER SECTION 12 A
• REGISTERED UNDER NITI AYOG
• REGISTERED UNDER CSR-1 FROM ROC
• All Compliances and reports assured
info@fii.org.in
www.fii.org.in
+91 98100 17267

FII-EVA ANNOUNCES MOU SIGNING CEREMONY

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

Promote your Business with FII

CONTACT US

Uditendu Verma , Managing Editor
+91-9599935527 | uditendu@gmail.com
www.fii.org.in

Reachover of FII News Letter

145 Countries
Pan India Coverage

www.fii.org.in

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

Prime Minister Narendra Modi will hit battleground Uttar Pradesh by holding a virtual rally on January 31, ahead of Assembly elections in the state. This virtual rally by the Prime Minister will cover five districts of Uttar Pradesh namely Shamli, Muzaffarnagar, Baghpat, Saharanpur, Gautambuddh Nagar (Dadri/Jewar) And it will cover 21 Vidhan Sabhas.

Former Prime Minister H D Deve Gowda on Monday welcomed Prime Minister Narendra Modi's decision to install the statue of Netaji Subhas Chandra Bose at in India Gate New Delhi. The JD(S) patriarch also recalled that he was Prime Minister during Bose's birth centenary year.

Amid a growing number of Covid cases in the country, Lok Sabha Speaker Om Birla on Tuesday said necessary arrangements for the upcoming budget session of Parliament are being made to enable members of Parliament perform their constitutional responsibilities. He also asserted that the "situation is under control" and all steps are being taken to mitigate the impact of the pandemic.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

India has said there must be "concrete progress" in ensuring that UN-proscribed terrorist entities do not get any tacit or direct support from Afghan soil or from terror sanctuaries based in the region, an apparent reference to Pakistan.

Abu Dhabi investment firm Chimera Capital said on Tuesday it closed its second venture capital (VC) fund at $10 billion, as it looks to find multi-million dollar opportunities in "growth-stage" companies.

Despite delivering a record number of cars in 2021, Elon Musk-run electric car maker Tesla lost nearly $109 billion in market valuation in a single day after its fourth-quarter earnings and outlook failed to impress the investors.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

Scheduled commercial banks will set up 75 digital banks in 75 districts to encourage digital payments, Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Tuesday. Presenting the Union Budget 2022-23, she also said e-passports with the embedded chip will be rolled out.

HDFC Bank, ICICI Bank and State Bank of India may be the biggest beneficiaries from the government's push to convert more than 1.5 lakh post offices into banking outlets as these lenders could tap into the nearly Rs. 15 lakh crores of savings in the post offices to sell other financial products like mutual funds and insurance.

The microfinance sector has urged Finance Minister Nirmala Sitharaman to increase the limit of credit guarantee scheme in the budget for 2022-23. In the budget representation to the ministry, the self-regulatory body (SRO) of MFIs said the sector is facing a few challenges in terms of higher credit costs and access to low-cost long term funds.

Finance minister Nirmala Sitharaman has announced that to foster further efficiency in the electric vehicle ecosystem, a battery swapping policy will be deployed.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

Tata Power is in advanced talks with investors, including Canadian Pension Plan Investment Board (CPPIB) as well as Singaporean sovereign fund Temasek Holdings and private equity firm General Atlantic to raise as much as $600-700 million (Rs 4478 crore - 5225 crore) for the renewable energy business at an equity valuation of around $6-7 billion.

Total outstanding dues owed by electricity distribution companies (discoms) to power producers dipped 5.1 per cent year-on-year to Rs 1,15,972 crore in February 2022, as per latest data. Discoms owed a total of Rs 1,22,226 crore to power generation firms in February 2021, according to portal PRAPTI (Payment Ratification And Analysis in Power procurement for bringing Transparency in Invoicing of generators).

Assam chief minister Himanta Biswa sarma said that Assam has attracted 16 ethanol projects worth Rs 3290 crore as a fallout of consortium of OMCs floated bids for long term ethanol procurement.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

The Centre has approved over 9,000 applications and sanctioned Rs 6,540 crore so far, for the development of agri-infra projects, Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said on Friday in Rajya Sabha. Tomar, in his written reply to the Rajya Sabha, said: "As on date, 16,026 applications for an amount of Rs 10,627 crore have been received on the AIF portal. Out of these, 9,019 applications for Rs 6,540 crore have been sanctioned."

Farmers are keen to use 'Kisan drones' to spray pesticides and nutrients on their crops provided they are available on rent at an affordable rate, some farmer organisations told ET.

Union Budget 2022: Rs 2.37 lakh cr for MSP, tech usage and chemical free farming for agri sector

The agriculture credit flow for the year 2020-21 stood at Rs 15,75,398 crore against the target of Rs 15,00,000 crore for the year, said The Economic Survey 2022-23. The agriculture credit flow target for 2021-22 has been fixed at Rs 16,50,000 crore, it added.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

Venture capital investors and startup founders are likely to benefit from a tax tweak announced in Budget 2022-23. The surcharge on long-term capital gains (LTCG) tax has been capped at 15% for all listed and unlisted companies, finance minister Nirmala Sitharaman said.

President Ram Nath Kovind on Monday addressed a joint sitting of the Parliament ahead of the Budget session. During his speech, the President said the Indian startup ecosystem is an example of the endless new possibilities that are rapidly taking shape under the leadership of our youth.

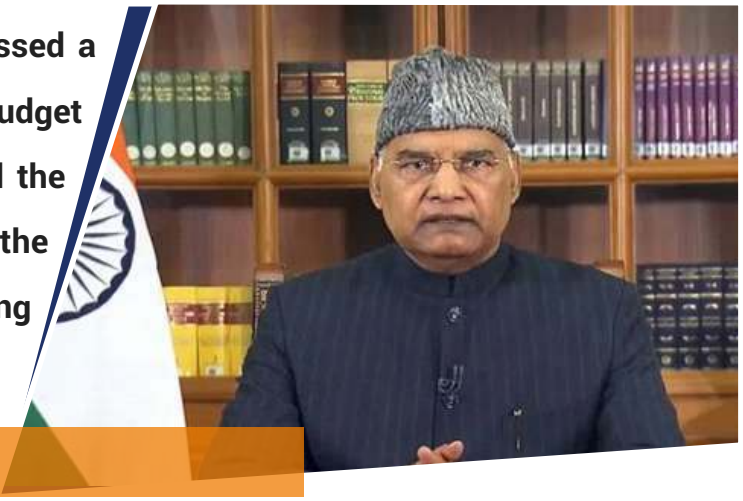

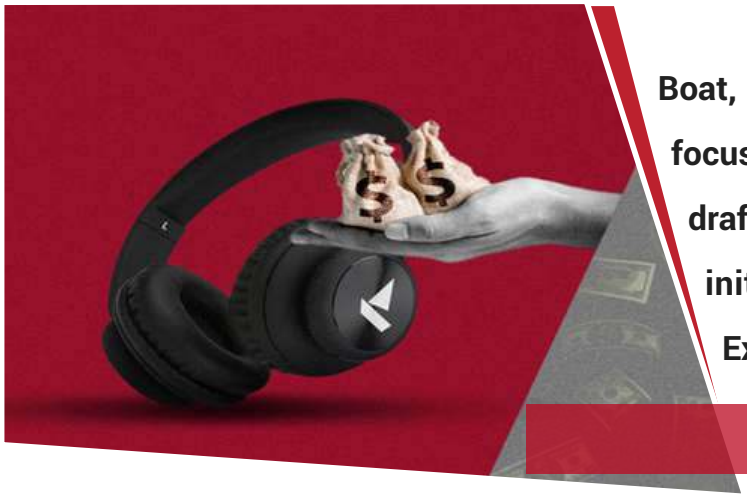

Boat, one of the largest direct-to-consumer, audio-focused electronics brands in India, is set to file a draft red herring prospectus for a Rs 2,000-crore initial public offering with the Securities and Exchange Board of India (Sebi) this week.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

Stakeholders of the country' logistics sectors have welcomed various pro-sector announcements in the Union Budget. Finance Minister Nirmala Sitharaman spelt out plans to take the Gati Shakti national master plan forward to spur the logistics infrastructure. The plan has received its first outlay of Rs 20,000 crore for 2022-23.

Healthcare experts have welcomed the Centre's announcement of a National Tele Mental Health Programme, especially in view of the long COVID, but highlighted that the Union Budget did not give adequate attention to other critical issues such as incentives for health insurance and skill development.

The government could open up on-the-job training for all sectors, besides bringing apprenticeship under one ministry or an umbrella body, as part of its efforts to significantly improve apprenticeship in India.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

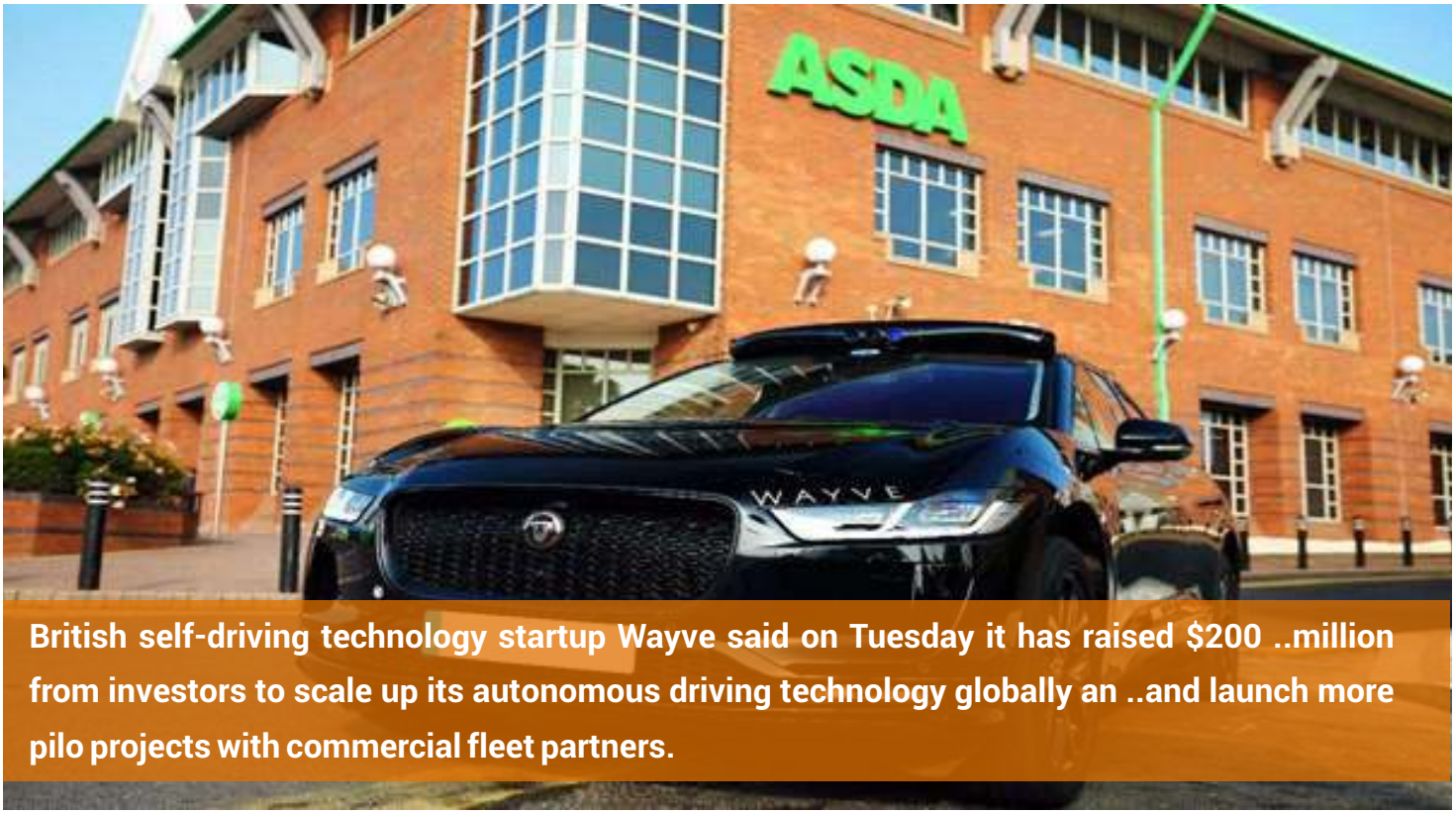

British self-driving technology startup Wayve said on Tuesday it has raised $200 ..million from investors to scale up its autonomous driving technology globally an ..and launch more pilo projects with commercial fleet partners.

German luxury carmaker Audi is evaluating the feasibility of producing electric vehicles locally in India while it seeks to reach threshold volumes for such a step to be successful, according to a senior company official. With the company deciding to go all-electric globally from 2033, it is a matter of time for local production of its electric cars, which has so far received a robust response in India.

British self-driving technology startup Wayve said on Tuesday it has raised $200 ..million from investors to scale up its autonomous driving technology globally an and launch more pilo projects with commercial fleet partners.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

IT major Infosys on Tuesday announced a Corporate Social Responsibility (CSR) collaboration with Tennis Australia to drive new digital learning and accessibility initiatives for under-represented communities. This programme is part of Infosys and Tennis Australia's Digital Innovation Partnership, which was recently extended until 2026, a statement said

A significant percentage of companies in India plan to increase their corporate social responsibility funding towards skilling and education in 2022, says a TeamLease EdTech survey. According to the survey, that covered over 100 companies across the country, nearly 70 per cent expressed an intention to increase their CSR (Corporate Social Responsibility) spending for education/skilling in the next fiscal.

Industry body CII has suggested the government include an additional 1 percent corporate social responsibility levy apart from the mandatory 2 per cent for one year in the upcoming Budget to encourage corporates to spend on providing Covid vaccine booster shots. The Confederation of Indian Industry (CII) has also urged state governments to lift the pandemic-induced restrictions on economic activity, arguing that the occupancy rate of hospital beds due to the Omicron variant of Covid is well within the manageable level.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

From tax to sector specific initiatives, Budget wants to propel manufacturing growth

Noting that women empowerment is one of the top priorities of the government, President Ram Nath Kovind said the 'Beti Bachao, Beti Padhao' initiative has yielded many positive results, including improvement in the number of girls enrolled in schools. President Kovind addressed the joint sitting of the two Houses of Parliament in which he highlighted the various initiatives taken by the government to provide women new opportunities of employment and equal participation in various fields.

Prime Minister Narendra Modi will interact with more than 150 startups from various sectors, including agriculture and health, on Saturday via video conferencing. Startups from various sectors such as enterprise systems, space, industry 4.0, security, fintech, environment besides agriculture and health will be part of this interaction, the PMO said on Friday

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

Shri Narayan Rane, Union Minister for MSME launched Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme (SCLCSS) for Services Sector.

A Memorandum of Understanding(MoU) was signed between electric two-wheeler maker Ather Energy and Electric Supply Companies (ESCOMs) of Karnataka in the presence of Chief Minister Basavaraj Bommai on Thursday for setting up 1,000 fast charging stations across the state. The ESCOMs would be the nodal agency to provide all technical support and government agencies would coordinate with them to share their available spaces for the charging stations, a release by CMO said.

Dalmia Bharat is planning to increase its cement capacity to more than 48 million tonnes (MT) by the end of fiscal 2024 from the current 35.9 MT by setting new plants and expansion of existing facilities, acquisitions and debottlenecking of production with an investment of Rs 9,000 crore

Private equity and venture capital firms invested $77 billion in 1,266 deals in 2021, a 62% increase from the $47.5 billion they pumped in 923 deals a year ago, according to a report by the Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA) and consultancy firm EY.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

News Highlights

IND U19 vs ENG U19 Final Highlights: India clinched the U-19 Cricket World Cup title for the fifth time after beating England by four wickets in the summit clash, riding on a sensational all-round show from Chandigarh boy Raj Angad Bawa on Saturday. Bawa shone with the ball with a sensational fiver (5/31) to help India shot England out for 189 before hitting a valuable 35 down the order to help India chase down the target of 190 with 2.2 overs to spare. Earlier, England opted to bat after winning the toss but they were shot out by India for 189 in 44.5 overs with pacer Bawa (5/31 in 9.5 overs) and Ravi Kumar (4/34 from 9 overs) sharing the spoils.

BEIJING 2022

Canadian figure skater Keegan Messing has been cleared to travel to Beijing for the Winter Games and is due to land on Monday morning after he had been delayed awaiting results of his COVID-19 tests, the Canadian Olympic Committee said. The 30-year-old, who finished 12th at the 2018 Pyeongchang Games, is theCanadian national champion and was unable to compete in the team event that started on Friday.

The 14-member squad will include four freestyle, four Greco-Roman wrestlers, four sparring partners and two coaches, a WFI release stated. Tokyo Olympics silver winner Ravi Dahiya and 2019 World Championships medallist Deepak Punia, along with six other Indian wrestlers, have been selected for a special camp in Teteven, Bulgaria from February 5 to 23

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

Tributes to Saraswati Putra Padma Bhushan Late Sh. Darshan Lal Jain

Fond Remembrance

Today is the day when we bid farewell to respected Babuji Shri Darshan Lal Ji Jain. He died at the ripe age of 94 years. His life is like a painting on a canvas. Ever since I remember, throughout my childhood days. I have seen him struggle to overcome any obstacle that came his way. He was never scared of anything. And always sticking to his principles and always working hard.I was lucky to be with him for most part of this journey, with his struggles, with his sorrows and with his happiness moments. He was deeply wedded to his convictions.There are several takeaways from his life that we learnt from him. His attachment to the youngsters and also inspiration to the next generations and his vision about the future.He would always lead from the front. These are the things for which he was admired by his fans and followers. Few things in life which we never fully agreed mutually, but we always respectfully agreed to disagree.

Today on his Punya Tithi, we take the opportunity to rededicate ourselves to his unfinished agenda. He had a number of achievements in his life. He lived his life deeply entrenched in RSS value systems at various levels in organisation. Years he spent in the freedom struggle. Then the time he spent for the revival of Saraswati river. His contribution to the education sector and rewriting of history. He has become immortal through his writings, through his thoughts, the inspiration and the values he imparted. Being honoured with Padma Bhushan was not an objective but just a milestone in the epic journey of his life. We, the team of FII, would continue to draw Inspiration from his life and ideals

Deepak Jain

Director General, FII

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

ARTICLES SUBMISSION

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

FII News Letter

MONTHLY NEWS LETTER
FOR GLOBAL AUDIENCE

Articles should be Min 800 - Max 1500 words.

**Articles should be sent as an attachment, in Word (.doc or .docx) Please do not send in .pdf format.
To submit, e-mail your article at uditendu@gmail.com.**

Include your first name, last name, and a contact e-mail address in the body of your message. Your name (but not your e-mail) will appear in the newsletter (unless you ask to be anonymous).

- **Related pictures are highly encouraged to be submitted along with your article.**
- **Include a short (1 sentence) caption of each image.**
- **Attach images to the same e-mail as your article submission.**

For more information, Please reach out

Managing Editor
Uditendu Verma
+91-9599935527
uditendu@gmail.com

visit www.fii.org.in

The need of fostering social entrepreneurship for sustainable development in India

Deepthi. B.

Research Scholar ABV-SME,
Jawaharlal Nehru University
FII Member

Throughout the world, there are societal challenges and severe societal needs that governments, non-governmental organizations (NGOs), and market groups fail to detect or adequately address. Nevertheless, social entrepreneurs are innovators who develop novel solutions to specific problems and back them up with novel business models. Presently, a wide range of opportunities exist for entrepreneurs in the Indian social entrepreneurship ecosystem. As the name suggests, social entrepreneurship is concerned with solving societal problems by starting businesses that benefit the community as a whole while still being profitable. Social entrepreneurship is a creative way to addressing the needs and requirements of a community and then generating products and services that suit those needs. In a nutshell, social entrepreneurs are those who are committed to making a positive impact on the world through their business. Social entrepreneurship is emerging as an innovative strategy to coping with complicated social concerns in today's entrepreneurship eco system.

There are a variety of reasons why social entrepreneurship has become more prevalent across the globe. In developing nations like India, social businesses identified and addressed a variety of issues that arose as a result of socioeconomic disparities. That is why social entrepreneurship is a critical component of development in developing countries. As an emerging nation, India faces unique societal problems and issues. The entrepreneurial activity and quick growth have been witnessed in India since the economy was opened up in the early 1990s. Although poverty and a lack of opportunities and resources persist for many citizens in the country, the economy is growing rapidly. As a means of boosting the economy across the entire territory, the government has increased funding for rural development and social welfare programmes.

Many entrepreneurs are putting money into the welfare programmes because they believe that individuals, not only governments or non-governmental organisations, can contribute new ideas, resources, and vigor to solving social and economic problems.Rural development in India is critical to the country's economic progress as villages are home to around 60 percent of India's population. Entrepreneurship is a vital aspect in rural development because it has the potential to significantly improve the economic and livelihood situation of villages by offering employment and income opportunities. In this kind of environment, social entrepreneurship has the key to reshaping

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

economic landscape from the ground up. Untapped markets in rural India includes microfinance, technological interventions in agriculture and commerce; basic education; skill education; digital connectivity and healthcare can all be efficiently explored as part of this endeavor. During the times of Covid19 pandemic also the aid efforts were actively supported by several social entrepreneurs and activists. When it comes to the reaction to the COVID-19 pandemic in India, social entrepreneurs have made it apparent that their on-the-ground participation and power to move as first responders in assistance of vulnerable members of society is critical. But despite all of these positive aspects, many of the social entrepreneurs fail to grow. Unfortunately, their tremendous ideas aren't fully realized in reality. To name a few reasons behind the social entrepreneurs' failure in India include, scarcity of skilled staff, lack of awareness and knowledge, trouble in acquiring finances, and lack of familial support. Despite these obstacles, some famous examples of social entrepreneurship exist, including Lijjat Pappad, Amul, and Gramin Banks. In India, the number of social entrepreneurs is growing, as are their efforts to offer low-cost solutions to society's plethora of maladies.

Today's society and globe are in desperate need of more leaders who would take a values-based approach to leading and actively fight to close current gaps and imbalances. Leaders who can 'respond' to the changing requirements of society while also committing to 'realizing' a new future that opens the door to a regenerative way of life. We need a revolution from people from different areas to come up with and implement effective, inventive, and long-term solutions to these issues. It's time for a new generation of social entrepreneurs to emerge in the wake of campaigns like Swachh Bharat. In emerging economies like India, new business models are needed to address complex social and environmental concerns. The path to becoming an entrepreneur and finding a solution to the problem would be challenging as usual. Due to our incapacity to pay greater rates, attracting the best employees will be a difficult issue. Above all, a strong sense of dedication and tenacity are essential. Entrepreneurs should be given a warm welcome by the community and society.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

Covid-19 What Humans Must Understand

Nidhi Behl Vats, FII Member

The sudden knock of Covid-19 has shaken the entire world. Yes, if the political analyst has to be believed then yes, it is sent by China. But my concern is how long do we keep criticizing China. It is tough to accept that it has come and we are unable to cope up with it. Yes, it's a fact be it at the Country level, at the societal level, or at an individual level. There isn't any satisfactory answer as to what is to be done and how.

During this, amidst I want to say that It has to be the survival of the fittest. Yes, this goes well with everyone and in the country at large or as an individual who is fighting with covid-19 in the hospital or at home. Did we ever look at our body, have we ever thought of our body or listen to it? No! This covid-19 wants us to go within and look for ourselves, to know our body well, and to listen to our body and as we listen to our body, it will connect us to nature immediately. I don't know how many of you have witnessed this but the matter of the fact is we are from nature and yes, it is through nature we have our existence.

So what we all are missing here –

THE HUMAN CONNECTION WITH THEIR SOUL

When was the last time you tried to connect yourself with your inner self? Do you know that there is an inner self within you? Have you ever felt that? If not, then this is the time, you must have experienced. I want to ask all the atheists today, why you want to pray to God today for the mercy of your or your loved ones' life? When God has never listened to you the entire life and you have never accepted that God exists, then why suddenly all Atheists have turned God loving? Don't ask for your life from God. And by the way, your death is in your hands, it's not in God's hands right so, chill no!

HUMAN CONNECTS WITH HUMAN (HUMANITY)

Why suddenly today we all are happy to help each other? Have you helped me before, only then I will help you, why we do not ask,? What is your name/religion/ designation, why we today do not ask? Are you influential, only then I should help you? Why we are helping today and have never thought to help before?

MONEY PERCEPTION

The first thing this lockdown and covid-19 have broken was your illusion with money. Yes, all those who have been boasting about money, lost their charm. As here it is not about money, so many wealthy people are at a loss today.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

NATURE'S CONNECTION OF HUMAN

Yes, we took birth coz nature supports us to live in a particular environment, hence we survive. What we humans are doing today? Cutting trees all around for own selfish motives! Is this is the reason the earth was supportive enough for us? Think. So, fine I may say that you are not cutting trees, but are you not buying all those things which are made from trees? Even if the options are available, are you not using plastic for your own comfort? Despite having one property, are you not investing in a building that is high rise? Are you not indirectly asking the builders to buy land, cut trees, and spoil the balance of nature? We never thought of these things, until this Covid, hit us hard.

SO WHAT REALLY WORKS –

01 **If you have been caring for nature in the past, Without boasting about it. You will be loved and you will come out safely.**

02 **If you have been helping people all the way, without expecting help in return, you will come out of Covid-19**

03 **If you have been working on your thoughts and self-healing, in the right manner. Trying to know more about your existence, you will come out of Covid-19.**

WHY ALL THIS IS NECESSARY

Coz these good deeds, come back many-fold in terms of the help, right thing available to you at right time. This happens all cozCovid-19 : Impact on Nature of the blessings and you will come out of this difficult situation. Today, covid made me realize the value of blessing and that's why my grandmother always said, you must help others as much as you can, without expecting. Also, you must give without telling to anyone.

This is going to be a new beginning for all those who have survived this pandemic. The world tomorrow is going to be a different world. Half of the people we have known today will not be there with us? If you are there alive, consider yourself a blessing and for sure you are going to have better tomorrow in the times to come.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

Patent for Business Idea in India

Amrita Nandy

Advocate & IPR Consultant, FII Member

Many entrepreneurs are interested in obtaining a patent for business idea or business model that has been invented by them to provide them a competitive advantage. However, not all inventions are patentable as per the patent laws and patent laws as well vary from country to country. In this article, we look at patent for business ideas, computer programs, mathematical models and algorithms as per the Indian Patent laws

What Can Be Patented?

As per the Patent Act, for an invention to be patentable, the invention must be a new product or process, involving an inventive step and capable of being made or used in an industry. It means the invention to be patentable should be technical in nature and should meet the following criteria –.

01 **Novelty:** The matter disclosed in the specification is not published in India or else where before the date of filing of the patent application in India.

02 **Inventive Step:** The invention is not obvious to a person skilled in the art in the light of the prior publication/knowledge/ document.

03 **Industrially applicable:** Invention should possess utility, so that it can be made or used in an industry.

As per the Indian Patent laws, a mathematical or business method or a computer programme per se or algorithms are not inventions and hence not patentable. Business methods or business models claimed in any form are not patentable subject matter. With the development of technology, innovative business models have also been established through e-commerce and related B2B and B2C business transactions. Hence, many patent applications are filed along with claims of technical features such as internet, networks, satellites, telecommunications etc. However, the exclusion of patenting business models or ideas apply to all business methods and, therefore, if in substance the claims relate to business idea, even with the help of technology, they are not considered to be a patentable subject matter in India.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

Patent for Computer Programs in India

Patent application for only a computer program, which is considered as a computer program per se are not patentable. Hence, patent applications involving computer programs stored in a computer readable medium and as such are not allowable. Even if the patent application claims that the invention involves a subject matter which is not a computer program, it is examined whether such subject matter is sufficiently disclosed in the specification and forms an essential part of the invention

Patent for Algorithms in India

Algorithms in all forms including a set of rules or procedures or any sequence of steps or any method expressed by way of a finite list of defined instructions, whether for solving a problem or otherwise, and whether employing a logical, arithmetical or computational method, recursive or otherwise, are not patentable in India.

Patent for Mathematical Models in India

Mathematical methods are considered to be acts of mental skill. A method of calculation, formulation of equations, finding square roots, cube roots and all other methods directly involving mathematical methods are therefore not patentable. With the development in computer technology, mathematical methods are used for writing algorithms and computer programs for different applications and the claimed invention is sometimes camouflaged as one relating to the technological development rather than the mathematical method itself. These methods, claimed in any form, are considered to be not patentable in India.

Inventions which are not patentable

Section 3 and 4 of **The Patents Act 1970** lay down the following inventions which are considered to be not Patentable:

- Inventions which are frivolous and not unique.

  Inventions causing or likely to cause injury to human, animal or plant life and health.
- Inventions causing or likely to cause danger to the environment.
- Inventions which are against morality and law.
- The mere formulation of an abstract theory or discovery of the scientific principle.
- Merely finding of any living or non-living substances occurring in nature.
- Finding any new property.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

- Just only a new use of known substances and process, machine and apparatus or admixtures of new substances and rearrangement of known devices. (note :- if it finally results in completely a new product or employs new reactant then it may fall within the ambit of the new invention).
- Inventions in the field of agriculture and horticulture merely developing methods related to agriculture and horticulture or biological processes for production or propagation of plants and animals.
- Inventions involving business method, a mathematical, algorithms or software program
- per se.
- Dramatics, artistic work or aesthetic creation like music composition or television production.
- Techniques of sports and mere rules of playing games.
- Information presentation.
- Topography related to Integrated Circuits.
- An invention which in effect a traditional knowledge or which is an aggregation of known properties of components which are traditionally known.
- Inventions in the field related to Atomic Energy.

Strictly, as per **Indian Patent Law**, an idea which is abstract or mathematical or business methods are usually excluded from the patents.

But those business methods and ideas which is the product of advancement of time and technology that has not yet been covered, described or excluded by the Indian Patent Law, having uniqueness and wider commercial application may well be considered for providing protection under Indian patent law.

However, the possibility of getting patent depends upon the way you put forth your application before the patent office and how well you describe the uniqueness, novelty, and application of your product, process or idea before the patent registrar.

Conditions for a business idea or invention to be patentable

As suggested by Indian Patent Law, an invention carries on an ability to have a new and interesting idea which results in a new product or a process which is capable of having wider commercial application.

(1) The **invention** must necessarily be new (novel), not priory used and known either through prior publication or claimed in the application for a patent anywhere in the world and in the country. It should not be part of state-of-the-art.

(2) As the inventions are to be judged by a person skilled in the art of the relevant area of technology, so it must not be so obvious to the skilled person. It has to involve some unique and different characters which are distinctive in features from the already existing inventions in a similar field.

(3) The invented product (idea, concept) or process must have the capability to be made used and widely applied in an industry with a greater economic and commercial significance.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

Contract Labour, Transition From Historical Use

Jorawer Singh
HRD Committee FII

The system of contract labour or outsourced employees or indirect employees, is all set to radically change, once the new Labour Codes get implemented. Most of the employers are not taking these changes seriously, due to shear lack of information, and perhaps more so, the mere magnitude of the disruption, is creating a resistance and blocking their thinking process.

The current legislation being so manageable, may also be giving a false hope of easily wriggling out of the new provisions.

Disruptive Change 1

The contractor labour employment in core areas (read-regular work), will **change from abolishable to abolished**. The abolishable part so far scarcely operative, for want of serious interest on the part of Governments, helped flourish this employment in core areas, regular work, & everywhere else, unbridled.

Disruptive Change 2

Those employed outside Principal Employer's premises were earlier excluded from the definition of workman, through a proviso to the definition, has now been done away, the new code therefore, **brings in its ambit "The Field Employees"** too.

Background:

The Contract Labour (R&A) Act, 1970, is in fact a legislation, which defeated the very purpose for which it was enacted, and, on the contrary, supported growth and exploitation of contract labour, at various scales, benefits being enjoyed by Contractors, Principal Employers, and Labour Department officials.

All the benefits conferred by this act were already available to these workers through alternative enactments, and though, it advocated against employment of contract labour in core areas and in work of regular nature, but, on ground the majority of contract labour has been employed defying this objective, the simple reason being that the abolition process laid down in the act is lengthy, time consuming and has worked only in a very few cases, that too, where, all stakeholders wanted it to be abolished due to their own vested interest. The registering and licensing authorities having a limited power to regulate the use of contract labour for regular jobs, only power being, a very specific recommendation to Government for abolition.

Why employs the Contract Labour?

(Non Genuine Outsourcing)

1. Where paying of minimum wages & PF & ESI is difficult for employer.
2. Where paying of annul/periodic wage like bonus/gratuity is a concern.
3. Where paying of terminal wage, like retrenchment /layoff compensation or notice period or taking permission to retrench from Govt is a concern.
4. Where employees are required to exceed the prescribed job parameters, to make exit easier for employer. where exit has to be on the basis of irrational reason like unpaid extended hours of overtime, asking employee to complete target irrespective of number of hours prescribed for work, give favours to the boss, overlook sexual harassment.
5. Where employer wish to deal with statutory authorities, like labour, pf, esi, factory inspection, and their gratification, indirectly through contractor, keeping its own image as corruption intolerant organisation.
6. Company Valuation: the contractor employees are considered variable cost while own employees are fixed costs, and more the variable costs, better the valuation.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

7. employer surveys, like "Hewitt best employer" survey, which process feedback only from on-roll employees, and rate "employee caring organisations" assigning a better brand image to the employer.
8. Employer's legal department having a false belief that outsourced employees will have a limited & controlled liability, and that all litigation can be taken care off through contractor indirectly.

The new code abolishes the above kind of outsourcing where ever contractor employees are not doing the "non-core work", the same being clearly defined as to what will constitute the "non-core work".

Genuine outsourcing

Where the contractor is expert in the service, which cannot be done by employer in a cost effective way of its own, like:

- **security services from G4S**
- **Pantry from café caféday**
- **Drivers & vehicles from Uber rides/taxi service company**
- **IT/software/hardware maintenance from Wipro IT**
- **Housekeeping from Wakefield**

(Only genuine deployment in the non-core areas, is permitted.)

Advantages and loopholes significantly reduced.

Outsourcing and contract labour are not the same. In outsourcing, the work is given to an external organisation and it is for that organisation to organise things to get the work done right from setting up the plant and machinery to managing the human resources.

Whereas in contact labour, the external organisation appoints the people on its payroll and deploys them to your organisation. These contract workers work in your premises and now includes, those in field under your supervision. The New Codes are all set to bust our following myths.

- Contract workers are generally not unionised; hence, industrial disputes are minimal.
- Salary bills can be minimised.
- If there is indiscipline, they can be sent home immediately by informing the contractor,
- If there is excess workforce due to economic recession their services can be withdrawn immediately by informing the contractor.
- Contract employees respond positively to incentive schemes since their salaries are lower & have aspirations to perform better to get "on-roll"
- Contract employees cannot compromise on productivity, quality, and good behaviour since continuance of their services depend upon these factors.
- The historical belief that people are motivated only by fear and greed, fully applies in the case of contract employees.
- "Work culture rating agencies", these employees can be safely excluded from survey whereby rating based on employee feedback can be favourably controlled.
- In case of net worth evaluation, contract employees are taken as running cost and not fixed cost, hence lower perceived liability gives higher valuations!
- The contractor employees cannot raise a demand notice or drag the principal employer to the Labour Court.
- With the above advantages gone, the outsourcing model needs a serious relook.

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII LEADERSHIP

International Affairs & Free Trade Zones Committee

Mr. Hitender Mehta
Chairperson

Startup & Skill Development Committee

Dr. Shailendra Vyas
Chairperson

Corporate Insolvency & Restructuring Committee

Mr. Sanjay Gupta
Chairperson

Goods & Services Committee

CA Mr. Atul Kumar Gupta
Chairperson

Fin-Tech Committee

Mr. Rajan Dogra
Chairperson

Media & IT Committee

Mr. Sanjeev Arora
Chairperson

Water Resource Committee

Maj. Gen G.D. Bakshi
Chairperson

Dr. Arvind Phukan
Co-Chairperson

Mr. N.K. Jain
Vice-Chairperson

Social Outreach Committee

Mr. Uditendu Verma
Chairperson

Dr. Anshul Dhingra
Co-Chairperson

Banking & Finance Committee

CA Mr. Yatinder Khemka
Chairperson

Agriculture Committee

Mr. Vijay Sardana
Chairperson

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

MSME Committee

Mr. Raman Saluja
Chairperson

Mr. Sanjay Daftari
Co-Chairperson

Mr. Kapil Malik
Vice-Chairperson

CSR Committee

Mr. Harbhajan Singh
Convenor

Ms. Payal Kanodia
Co-Chairperson

Road Safety & Traffic Awareness Committee

Mr. Arvind Singhla
Chairperson

Women Empowerment

Ms. Vineeta Jerath Grover
Chairperson

Advocate Ms. Ritu Kapoor
Co-Chairperson

Health Committee

Dr. Vandana Thakran
Chairperson

Disaster Risk Reduction Committee

Mr. JP Singh
Convenor

Sports & Recreation Committee

Mr. GL Khanna
Chairperson

Mr. Nikhil Gupta
Co-Chairperson

Support Children with Special Needs

Ms. Neena Wagh
Chairperson

Defence Committee

Maj. Gen. Ashwani Kumar Channan
Chairperson

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII PATRONS

Ch. Birender Singh

Former Union Minister for Steel, Government of India

Ms. Baroness S .Verma

Member, House of Lords, UK

Maj. General G.D. Bakshi

War Veteran, India

Mr. Kanwaljit Singh Bakshi

Ex-MP, New Zealand

Mr. Rambilas Sharma

Former Education Minister, Haryana India

Ms. Chanda Chaudhary

MP, Nepal

Mr. Atul Kulkarni

Management Consultant, India

Mr. Ashwin Jauhar

Social Worker

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII CORE GROUP

Mr. Deepak Jain

Director General

Mr. Hitender Mehta

Chairperson, International Affairs Committee

Dr. Shailendra Vyas

Chairperson, Startup Committee

Mr. Uditendu Verma

Addl. General Secretary

Dr. Dravya Jain

Advisor

Mr. Sanjiv Arora

Chairperson, Media & IT

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII INTERNATIONAL TEAM

Ms. Rachna Nath General Secretary, USA
Mr. Sameer Jain Vice President, FII- US Chapter ,
Dr. Arvind Phukan Executive Member, FII- US Chapter ,
Mr. Babu Raman K Joint Secretary, FII-US Chapter
Mr. Sunil Hali Advisor, FII-US Chapter
Ms. Nupur Jain Tresurer, FII-US Chapter
Ms. Ramya Ranganathan Executive Member, FII- US Chapter
Mr. Mark Bordoloi Executive Member, FII- US Chapter
Mr. Akshay Jain Executive Member, FII- US Chapter
Ms. Radhika Siva Executive Member, FII- US Chapter
Dr. Suresh Gupta Mentor & Executive Members
Ms. Hina Trivedi Member, FII-US Chapter
Mr. Rajan Gangahar Advisor, FII-US Chapter
Mr. Vidya Bhushan Dhar Country Co-ordinator, Canada
Mr. Shobhan Saxena Country Co-ordinator, Brazil
Mr. Ashok Verma Country Co-ordinator, UK
Mr. Lalit Sharma Convenor, Europe
Mr. Nishant Jain FII -Sweden
Mr. Raveendra Kulkarni President, Germany Chapter
Mr. Deeban Mathivanan General Secretary, Germany
Mr. Bopanna Monnanda Vice president, Germany Chapter
Mr. Kiran Kishore G Vice president, Germany Chapter
Mr. Anirudh Mohan Executive Members
Mr. Vivek Tayal President, France Chapter
Mr. Pankaj Dhawan Vice President France Chapter,
Mr. Ramesh Bhavsar Treasures, France Chapter.
Mr. Paul Sanjeev Kumar Vice President, France Chapter
Mr. Nagapraveen Jayaprakash Advisor, France Chapter
Dr. Adarsh Gupta Jt. Secretary, FII- France Chapter
Mr. Rajeev Kumar Advisor to Board, FII-France Chapter
Mr. T. Srinivasa Reddy Country Co-ordinator, Russia
Mr. Avinash Mannan Country Co-ordinator, Kuwait
Mr. Rajendra Khimesra Chairman, Thailand
Mr. D.K. Bakshi Country Co-ordinator, Thailand
Mr. Anurag Saxena Country Co-ordinator, Singapore
Ms. Deepa Gupta Co-ordinator, Australia
Mr. Giri Gupta Country Co-ordinator, New Zealand
Mr. Sanjay Srivastava Convenor, West Africa
Mr. Parimal Vipani Country Coordinator, Nigeria
Mr.Sudhir Rathore Vice President

Mr. Jai Prakash Pandey Jt. Seceratary
Mr. Sanjay Jha Teasurer
Mr. Anirudh Singh Jt. Treasurer
Mr. Sanjeev Tondon Advisor
Mr. Sanjay Jain Advisor
Mr. Kirti Sudhanshu Advisor
Mr. Nitin Nagine Director
Mr. Y Y Singh Director
Mr. Robin Puri Director
Mr. Rajneesh Srivastava Director
Mr. Shishir Verma General Secretary, Nigeria
Mr. Kiran M Gosavi President, Nigeria
Mr. Vijay V Gurav Country Convenor- Cameroon
Mr. Sujoy Ghosh Vice President & Convenor- Benin
Mr. Dheerendra Chauhan Jt. Convenor- Benin Republic
Mr. Prabhat Mehta - Ghana Jt. Convener- Ghana
Mr. Sanjay Verma Conveor, Ghana
Mr. Nishant Bhatnagar Convenor- Zambia
Vikas Arya Convenor- Madgaskar & Jt Convenor- Ghana
Mr. Kishore Shapriya Co-ordinator, Tanzania
Mr. Jatin Kamdar Coordinator- Kenya
Mr. Jakson Dukpa Country Co-ordinator, Bhutan
Ms. Chanada Chaudhary , Nepal
Mr. Ved Prakash Sharma, FII Country Co-ordinator, Nepal
Dr. Ramesh Kumar Shardha Country Co-ordinator, Pakistan
Mr. S. Niranjan Country Co-ordinator, Srilanka
Mr. Swapan Chaudhary Country Co-ordinator, Bangladesh
Mr.Ajit Kumar Convenor- Bengaladesh
Mr. Pankaj Kumar GS - Bengaladesh
Md. Tofayel Ahmed Almas JS - Bengladesh
Mr. Ezaz Ahmed Bengladesh
Mr. Salim faisal bhuiyan Bengladesh
MD Rafezur Rahman Bengladesh
Mr. Makoto Saito Chairman, FII Chapter Japan
Mr. Abhilash D. Pandya President, Norway chapter
Mr. Atul General Secretary, Norway Chapter
Mr. Ravi Shroff Vice President, Norway Chapter
Mr. Manoj Thakur Secretary, Norway Chapter
Mr. Navneet Kumar Treasurer, Norway Chapter
AMB Ms. Zena Chung, South Korea

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII INTERNATIONAL PRESENCE

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

NORTH AND SOUTH AMERICA

US
Canada
Brazil
Mexico

EUROPE AND UK

UK
Sweden
Germany
France
Norway
Netherlands
Russia

AUSTRALIA OCEANIA

FIJI
Australia
New Zealand

MIDDLE EAST

Kuwait
Israel
UAE

REST OF ASIA

Japan
China
South Korea
Taiwan
Vietnam
Thailand
Malaysia
Singapore

AFRICA

South Africa
Nigeria
Cameroon
Benin Republic
Ghana
Zambia
Madgaskar
Tanzania
Kenya
Chad
Mauritius

INDIAN SUBCONTINENT

Bhutan
Nepal
Pakistan
Srilanka
Bangladesh
India

02022022

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII International MOUs

Japan

Vietnam

South korea

Nepal

Thailand

UK

Singapore

New Zealand

Germany

02022022

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

INDIAN STATES TEAM

Mr. Deepak Jain
Director General, FII

Mr. Harbhajan Singh v
President, Haryana Chapter

Mr. Raman Saluja
Vice President, Haryana Chapter

Mr. Deepak Maini
General Secretary, Haryana Chapter

Mr. Yudhveer Kaura
Co-ordinator, Punjab State

Mr. Dinesh Gupta
Co-ordinator, J&K State

Mr. Chiranjeev Singh Thakur
President, Himachal State

Mr. Yograj Chhoker
Vice President, Himachal Chapter

Mr. Ranesh Rana
Organisation Secretary, Himachal Chapter

Ms. Neeta Boochra
Co-ordinator, Rajasthan State

Mr. Shivam Bansal
Co-ordinator, Gujarat State

Dr. Rajesh Kumar Garg
Co-ordinator, Kanpur UP

Mr. Sunil Garg
Co-ordinator, West UP

Mr. Bharat Aggarwal
Co-ordinator, Bihar State

Mr. Gautam Jha
Chairman, Committee-Bihar

Mr. Yogendra Tulsyan
Co-ordinator, Jharkhand

Mr. Samir Pal
Co-ordinator, West Bengal

Mr. Dipanker Sarkar
Co-ordinator, West Bengal

Mr. Badarudheen Mohamed
General Secretary, Kerala Chapter

Mr. Sanjay Sethi
Co-ordinator, Madhya Pradesh

Mr. Amitabh Nigam
Co-ordinator Vidarbha Region

Mr. Siddharth Khosla
President, Nagpur Chapter

Mr. Sanjay Dhavalikar
Co-ordinator, Maharashtra

Mr. Sanjay Dhavalikar
Co-ordinator, Goa

Mr. Mukesh Sakhuja
Co-coordinator, Delhi State

Mr. Suresh Anand
Co-ordinator, Tamilnadu State

Ms. Shikha Sharma
Co-ordinator, Karnataka State

Mr. Tashi Khachu
Co- ordinator, Ladakh UT

02022022

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FII PARTNERS

02022022

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

CREATING OPPORTUNITIES...BUILDING NATION!!

JOIN FII

BUSINESS|NETWORK|KNOWLEDGE

FII-INTERNATIONAL NETWORK CHARTER

- Assisting Overseas Businesses for setting up operations in India.
- Promoting an environment of strong business relationships of India with growing Economies.
- Strengthening Indian Diaspora, Businesses and Professionals.
- Promoting Brotherhood and Business Networking among Indian Diaspora.
- Creating awareness for Indian Diaspora to Business Opportunities in India.
- International Conferences on side-linesof Pravasi Bhartiya Diwas to facilitate networking across eminent businesspersons.
- Partnerships with International Associations.
- Strengthening of relationships with Indian Consulates abroad.
- Celebration of Indian & International Holidays in synergy to recognize and promote International Brotherhood.

Membership facility services through **www.fii.org.in**

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

CREATING OPPORTUNITIES...BUILDING NATION!!

JOIN FII

BUSINESS|NETWORK|KNOWLEDGE

FII Membership Advantages

As a member of FII, you become empowered as you gain access to a world of opportunities.

Govt. Policies

1.Opportunity to contribute to making of "Atmanirbhar Bharat"

2. Be up to date about govt. schemes to gain maximum advantage for business interests

3.Contribute to formation of Business friendly laws and policies in association with Govt.

4.Proper Representation of Industry

Networking

1. Networking opportunities with Indian and Global Leaders
2. International Business Heads
3. Across Industrial Sectors
4. Platform to meet global business heads and political leaders

Events & Other Deliverables

1.WhatsApp Group Inclusion facilitating networking with business contacts in FII Chapters

2. Complimentary subscription to monthly Newsletter highlighting new developments and business opportunities in India

3.Weekly Awareness programme "Talk with an Expert" inviting Industry experts to discuss policies, new laws, startups, MSMEs, Legal, Financial Issues, Corporates etc

4.General body meeting with all FII members

5.Participation in development activities like webinars, symposiums, workshops, seminars, buyer seller activities and any other activity related to industry

Professional Help from FII

1.Dedicated Committees for

- MSME
- Defence
- Water Resources
- Goods & Service Tax
- CSR
- International Affairs & Free Trade Zones
- Human Resource Development
- Agriculture
- Banking & Finance
- Startup & Skill Development
- Social Communication & Outreach

2. Credit Counselling, Advice on GST & Taxes, Advice on loans, Recovery of Delayed/ Stuck Payments, Advice on Subsidies & Grants

3.We provide help in revival of sick units with experts on every domain

4.Support for business development through participation in Exhibitions within/outside India and plan for visit to International Trade Fairs

5. Empower Indian businesses in their global outreach for business expansion.

6. Overseas Delegations

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN

YUVITECH ENGINEERING

Solution Industry With Loyal Services

INDUSTRIAL SOLUTION

AUTOMATION | ELECTRICAL | PLANT MONITORING
PLANT OPTIMIZATION | ENERGY SOLUTIONS

Difference In Our Way Of Doing

Standardization | Cost Effective | Defined Process
Manufacturing Capability |Prompt Response

Follow Us

Our Technical services are conducted in accordance to our regulated high quality standards and close supervision to meet our partners expectations and needs.

www.yuvitechengineering.in

Email-yuvitechengineering@gmail.com | Mob: +91-9319108002

Future Industrial Revolution To Make a Smart Industry

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

Federation of Indian Industry (FII), a not-for-profit organization, is an advisory interface between the Government and Industries. A creation of Industrialist & Philanthropist, Mr.Deepak Jain, with an objective to provide a structured and comprehensive advise and information to Indian Entrepreneurs, Foreign Investors and Government on business environment, prevalent laws, operational intricacies, and implementable solutions. FII offers a platform for networking and relationship building within and across the Industrial sectors, policy makers, and the International business fraternity.

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

FEDERATION OF INDIAN INDUSTRY

CREATING OPPORTUNITIES...BUILDING NATION!!

To get our News Letter :

Whatsapp Your Name and Number: +91-98100 17267

• Fll newsletter being circulated in more than 145 countries of the World.

For suggestions and Advertisement please write to us at: info@fii.org.in

DISCLAIMER

The report is prepared using information of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. The report has been prepared from various public sources and the information received from these sources is believed to be reliable. The information available in the report is selective and subject to updation, revision and amendment. While the information provided herein is believed to be accurate and reliable, Fll does not make any representations or warranties, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of such information and data available in the public domain

Monthly Newsletter for Private Circulation Only

COPYRIGHT PORTAL WWW.FII.ORG.IN